▪ चैत्र शुक्ल - 5 ▪ संवत 2081 ▪ वर्ष - 12 ▪ अंक - 244 ▪ पृष्ठ - 8 ▪ रु. 5/- चेन्नई » गुरुवार » 03-04-2025 ▪ www.dakshinbharat.com ▪ Email : chennai@dakshinbharat.com

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

தக்ஷின் பாரத் ராஷ்ட்ரமத் | தினசரி ஹிந்தி நாளிதழ் | चेन्नई और बेंगलूरु से एक साथ प्रकाशित

4 राजस्थान में 5 हजार करोड़ की लागत से नेशनल हाइवे बनेगें : दीया कुमारी

6 'घिली' की दुनिया बनाम हकीकत : कला, रोजगार और मौलिकता का संघर्ष

7 राशि खन्ना ने अपनी एनर्जेटिक जिम रूटीन से फिटनेस को बनाया मजेदार!

फर्स्ट टेक

कर्नाटक उच्च न्यायालय का छह सप्ताह में बाइक टैक्सी सेवाएं बंद करने का आदेश

बेंगलूरु/भाषा। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बुधवार को ऐप आधारित टैक्सी सेवाएं देने वाली कंपनियों को छह सप्ताह के भीतर राज्य में बाइक टैक्सी सेवाएं बंद करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि जब तक राज्य सरकार मोटर वाहन अधिनियम के तहत उचित दिशानिर्देश अधिसूचित नहीं करती, तब तक बाइक टैक्सी नहीं चल सकती। न्यायमूर्ति बी एम श्याम प्रसाद की एकल पीठ ने राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि निर्धारित समय के भीतर बाइक टैक्सी का परिचालन बंद कर दिया जाए। यह निर्देश तब आया जब बाइक टैक्सी भी संचालित करने वाली ओला, उबर और रैपिडो जैसी कंपनियों ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और राज्य सरकार को बाइक टैक्सी चलाने के लिए नीति तैयार करने को आवश्यक निर्देश देने की मांग की। अदालत ने बाइक टैक्सी संचालकों को छह सप्ताह के अंदर परिचालन बंद करने का आदेश देते हुए राज्य सरकार को इस संबंध में दिशानिर्देश तैयार करने का निर्देश दिया।

एयर इंडिया का पहला बी777 विमान नवीनीकरण के बाद लौटा

नई दिल्ली/भाषा। एयर इंडिया को बुधवार को भारी नवीनीकरण के बाद पहला बोइंग 777-300 ईआर विमान प्राप्त हुआ। कंपनी के अधिकारियों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि शेष 12 विमानों का नवीनीकरण वर्ष के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। पिछले साल शुरू होने वाला पुराने बी777 विमानों की मरम्मत का काम आपूर्ति शृंखला संबंधी समस्याओं के कारण विलंबित हो गया है, इसलिए एयरलाइन ने इन विमानों को नया रूप देने का फैसला किया है। विमान को अच्छी तरह से नया रूप देने में नए कालीन, सीट कवर, कुशन और टूटी सीटों को ठीक करना शामिल है। एयर इंडिया के पास कुल 40 पुराने बड़े आकार वाले विमान हैं। इनमें 13 बी777 और 27 बी787 हैं।

म्यामांर में भूकंप: मृतक संख्या 3000 के पार

बैंकाक/एपी। म्यांमार में सत्तारूढ़ सेना ने देश में जारी गृहयुद्ध को लेकर बुधवार को अस्थायी संघर्षविराम की घोषणा की ताकि 7.7 तीव्रता के भूकंप के बाद राहत प्रयासों में मदद मिल सके। इस भूकंप में 3,000 से अधिक लोगों की मौत हुई है। सेना की उच्च कमान की यह घोषणा बुधवार देर शाम सरकारी टेलीविजन एमआरटीवी पर प्रसारित की गई। घोषणा में कहा गया कि यह संघर्षविराम 22 अप्रैल तक जारी रहेगा ।

सूर्यास्त 03-04-2025 6:20 बजे | सूर्योदय 04-04-2025 6:03 बजे

BSE	NSE
76,617.44	23,332.35
(+592.93)	(+166.65)

सोना	चांदी
9,244 रु.	110,000 रु.
(24 कैरेट) प्रति ग्राम	प्रति किलो

मिशन मंडेला

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

दक्षिण भारत का लोकप्रिय हिन्दी दैनिक

epaper.dakshinbharat.com

कैलाश मण्डेला, मो. 9828233434

अस्थाई राज

इतनी भी नाराजी क्यों हैं,
सत्ता तो आनी-जानी।
ऐसी भाषा बोल रहे क्यों,
जैसे हो दुश्मन जानी।
बोलो कब ठहरा है अब तक,
बहती नदिया का पानी।
लोकतंत्र में नहीं चलेगी,
कभी किसी की मनमानी।।

वक्फ कानून संसद का है, इसे सभी को स्वीकार करना पड़ेगा : अमित शाह

■ वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 लोकसभा में भारी बहुमत से हुआ पारित

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में विपक्ष पर आरोप लगाया कि वह वक्फ पर प्रस्तावित कानून नहीं मानने की धमकी दे रहा, लेकिन यह संसद द्वारा पारित किया गया कानून होगा और इसे सभी को स्वीकार करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि वोट बैंक की राजनीति के लिए यह डर फैलाया जा रहा है कि वक्फ विधेयक मुसलमानों के धार्मिक मामलों और उनके द्वारा दान की गई संपत्तियों में दखल है।

सदन में वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 पर चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए शाह ने स्पष्ट किया कि इसके कानून का रूप लेने के बाद इसे पूर्व प्रभाव से लागू नहीं किया जाएगा, जबकि (विपक्ष द्वारा) मुस्लिम भाइयों को इस बहाने डराया जा रहा है। उन्होंने कहा, ''(विपक्षी दल के) एक सदस्य ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय इसे स्वीकार नहीं करेगा। यह क्या धमकी है...यह संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा।

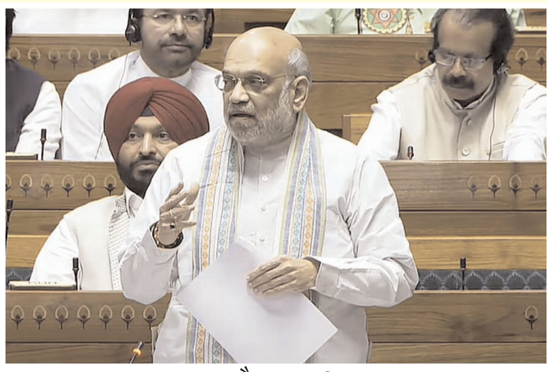

यह भारत सरकार का कानून है, हरेक (नागरिक) के लिए बाध्यकारी है (और) इसे स्वीकार करना पड़ेगा।'' उन्होंने कहा कि वक्फ की संपत्तियां बेच खाने वाले को इससे बाहर निकालने के लिए यह कानून लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस संशोधन विधेयक का उद्देश्य औने-पौने दाम पर सौ साल के लिए वक्फ की जमीन किराये पर देने वाले लोगों को पकड़ना है।

शाह ने कहा, ''यह पैसा जो चोरी होता है, उसे पकड़ने का काम वक्फ बोर्ड करेगा।'' उन्होंने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके राज्य में (वक्फ की जमीन के लिए) जो मिलीभगत चल रह रही है वह अब नहीं चलेगी।

ओवैसी ने लोकसभा में वक्फ विधेयक के मसौदे की प्रति फाड़ी

नई दिल्ली/भाषा। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार रात को लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 का विरोध करते हुए इसके मसौदे की प्रति फाड़ दी। सदन में विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए ओवैसी ने कहा कि यह भारत के ईमान पर हमला है और मुसलमानों को अपमानित करने के लिए लाया गया है। उन्होंने कहा, ''इस विधेयक को लाकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समूह के खिलाफ जंग छेड़ दी है।''

वक्फ की 90 प्रतिशत से अधिक संपत्ति विवादित : आरिफ मोहम्मद खान

मथुरा, (उप्र)/भाषा। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने बुधवार को कहा कि वक्फ की 90 प्रतिशत से अधिक संपत्ति विवादित है और मामले अदालत में लंबित हैं। यहां पत्रकारों से बातचीत के दौरान राज्यपाल खान ने यह बात कही। खान ने कहा, कॉलेज, विश्वविद्यालय या अनाथालय चलाने जैसे धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल की जा रही वक्फ संपत्ति ढूंढना मुश्किल है और इससे केवल अमीर वर्ग के उद्देश्य की पूर्ति की जा रही हैं। इससे पहले महावन तहसील के अंतर्गत आने वाले लोहवन में दो नए पुनर्निर्मित सरकारी स्कूलों का उद्घाटन करते हुए राज्यपाल ने परिवर्तन में शिक्षा की भूमिका का उल्लेख किया। उन्होंने समाज के उत्थान के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया।

जामनगर में वायुसेना का लड़ाकू जेट विमान दुर्घटनाग्रस्त

एक पायलट सुरक्षित बचा, दूसरा लापता

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जामनगर/भाषा। गुजरात के जामनगर वायुसेना स्टेशन के पास बुधवार रात भारतीय वायुसेना का एक जगुआर लड़ाकू विमान एक गांव में प्रशिक्षण मिशन के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस घटना में एक पायलट सुरक्षित रूप से बाहर निकल आया, जबकि दूसरा पायलट लापता है। पुलिस अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

जिला पुलिस अधीक्षक प्रेमसुख

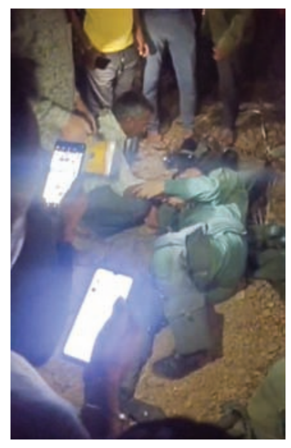

देलू ने बताया कि जामनगर शहर से लगभग 12 किलोमीटर दूर सुवरदा गांव के एक खुले मैदान में लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें आग लग गई। इस विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारणों का पता नहीं चला है। देलू ने कहा, ''दुर्घटना से पहले एक पायलट सुरक्षित रूप से विमान से बाहर निकल गया, जबकि दूसरा अब भी लापता है। दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद विमान में आग लग गई। पुलिस और दमकलकर्मी मौके पर पहुंच गए हैं तथा लापता पायलट की तलाश शुरू कर दी है।''

आज के आदर्श हैं शिवाजी महाराज

शिवाजी महाराज ने आक्रमणकारियों से युद्ध हारने की लंबी परंपरा खत्म की : संघ प्रमुख मोहन भागवत

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नागपुर/भाषा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बुधवार को कहा कि मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज ने भारत में आक्रमणकारियों से लगातार युद्ध हारने की लंबी परंपरा खत्म की। उन्होंने शिवाजी महाराज को विदेशी आक्रांताओं को करारा जवाब देने वाला पहला योद्धा करार दिया।

नागपुर में एक पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भागवत ने कहा कि विदेशी आक्रमणकारियों से युद्ध हारने की परंपरा सिकंदर महान के समय से चली आ रही थी और यह इस्लाम के प्रसार की आड़ में किए गए बड़े आक्रमणों के दौरान भी जारी रही।

उन्होंने कहा, लड़ाई हारने और साम्राज्यों को नष्ट होते देखने की यह परंपरा सदियों

तक जारी रही, जिसे विजयनगर साम्राज्य या राजस्थान के शासक भी खत्म नहीं कर सके।

संघ प्रमुख ने इस बात पर जोर दिया कि 17वीं शताब्दी में मराठा साम्राज्य की स्थापना करने वाले शिवाजी महाराज ऐसे आक्रमणों का करारा जवाब देने वाले पहले योद्धा थे।

उन्होंने कहा, शिवाजी महाराज पहले योद्धा थे, जिन्होंने ऐसे हमलों और आक्रमणों का करारा जवाब दिया। विदेशी आक्रमणकारियों से एक के बाद एक युद्ध हारने का युग शिवाजी महाराज के उदय के साथ समाप्त हुआ, क्योंकि उन्होंने इसका समाधान पेश किया।

भागवत ने कहा कि शिवाजी महाराज को 'युगपुरुष' कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने देश में मुगल आक्रमण सहित अन्य आक्रमणों के चक्र को रोक दिया था।

उन्होंने याद किया कि शिवाजी महाराज कैसे आगरा में मुगल बादशाह औरंगजेब की कैद से भाग गए थे, जिससे उन्हें क्षेत्रों को सफलतापूर्वक वापस हासिल करने में मदद मिली।

संघ प्रमुख ने कहा, उन्होंने पहले शांति समझौते में जो कुछ भी (छोड़ने) पर सहमति जताई थी, उसे वापस हासिल कर लिया और छत्रपति शिवाजी महाराज के रूप में खुद का राज्याभिषेक किया। उनके राज्याभिषेक से देश में ऐसे आक्रमणकारियों का अंत हो गया।

उन्होंने बाद में अन्य क्षेत्रीय शासकों के नेतृत्व में शुरू हुई प्रतिरोध की लहर का जिक्र किया, जो मराठा शासक से प्रेरित थे।

वैष्णव ने लोस में कहा :

और अधिक ट्रेनों में स्थानीय व्यंजन उपलब्ध होंगे

नई दिल्ली/भाषा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को कहा कि ट्रेनों में क्षेत्र के आधार पर स्थानीय व्यंजन उपलब्ध कराये जाएंगे और इस सिलसिले में दक्षिण रेलवे के तहत एक महत्वपूर्ण प्रयोग शुरू किया गया है। रेल मंत्री ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान द्रमुक सदस्य सुमति टी. के एक सवाल का जवाब देते हुए यह जानकारी दी। द्रमुक सांसद ने मंत्री से यह अनुरोध किया था कि तमिलनाडु में परिचालित होने वाली वंदे भारत ट्रेनों में दक्षिण भारतीय व्यंजन भी उपलब्ध होने चाहिए। वैष्णव ने कहा कि रेलवे ने यात्रियों को स्थानीय व्यंजन परोसे जाने को सुनिश्चित करने के लिए दक्षिण रेलवे में एक महत्वपूर्ण प्रयोग किया है।

तमिलनाडु विधानसभा ने किया

कच्चातीवु द्वीप को वापस लेने का प्रस्ताव पारित

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। तमिलनाडु विधानसभा ने बुधवार को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें केंद्र से अनुरोध किया गया है कि वह राज्य के मछुआरों के पारंपरिक मछली पकड़ने के अधिकारों की रक्षा के लिए स्थायी समाधान के रूप में श्रीलंका को सौंपे गए कच्चातीवु द्वीप को वापस ले। मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को इस मुद्दे पर गहन चर्चा के बाद मुख्य विपक्षी दल अखिल भारतीय अन्नाद्रमुक मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) ने समर्थन दिया। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और कांग्रेस ने भी इसका समर्थन किया।

मुख्यमंत्री ने सभी से पार्टी लाइन से ऊपर उठकर सरकार के प्रस्ताव का समर्थन करने की अपील की, क्योंकि यह मछुआरों के कल्याण से जुड़ा है। प्रस्ताव में कहा गया है, कच्चातीवु द्वीप को वापस लेना तमिलनाडु के मछुआरों के पारंपरिक मछली पकड़ने के अधिकारों की रक्षा करने और श्रीलंकाई नौसेना के कारण उन्हें होने वाली परेशानियों को कम करने का एकमात्र स्थायी समाधान है।

प्रस्ताव के अनुसार, उपर्युक्त बातों पर विचार करते हुए यह सम्मानित सदन सर्वसम्मति से केंद्र सरकार से आग्रह करता है कि वह भारत-श्रीलंका समझौते की तत्काल समीक्षा करे और कच्चातीवु द्वीप को वापस पाने के लिए सभी कदम उठाए। सदन भारत के माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह करता है कि वह श्रीलंका की अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान सद्भावना के आधार पर हमारे सभी बंदी मछुआरों को रिहा कराने तथा उनकी जब्त नौकाओं को वापस कराने के लिए श्रीलंका सरकार से बातचीत करें।'' भारत ने 1974 और 1976 में समझौतों के माध्यम से कच्चातीवु द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया था।

राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद को एम्स में भर्ती कराया गया

नई दिल्ली/भाषा। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद को बुधवार को इलाज के लिए यहां अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में भर्ती कराया गया। सूत्रों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 76 वर्षीय नेता को एम्स के हृदय रोग विज्ञान के प्रोफेसर डॉ. राकेश यादव के नेतृत्व वाले 'कार्डियो-न्यूरो सेंटर' की 'कार्डियो क्रिटिकल केयर यूनिट' में भर्ती कराया गया है। सूत्रों के मुताबिक, डॉक्टरों की एक टीम उनकी स्थिति पर नजर रख रही है। कुछ समय के लिए पटना के एक अस्पताल में भर्ती कराए जाने के बाद उन्हें रात करीब नौ बजकर 35 मिनट पर इलाज के लिए यहां स्थित एम्स लाया गया। पटना में पत्रकारों से बात करते हुए उनके बेटे और राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू प्रसाद की पीठ और हाथ पर घाव हो गए हैं, जिनका उन्हें दिल्ली में ऑपरेशन के जरिए उपचार होने की उम्मीद है। पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी ने कहा, ''लालू जी दोपहर दिल्ली जाने के लिए हवाई अड्डा पहुंचे। मेरी मां राबड़ी देवी उनके साथ थीं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर नई पीढ़ी के अंदर उत्साह : प्रधान

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। सरकार ने बुधवार को संसद में कहा कि राज्यों में धरातल पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति का कार्यान्वयन हो रहा है और इस नीति को लेकर नयी पीढ़ी में काफी उत्साह है।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों के जवाब में कहा, ''राज्यों में धरातल पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति का कार्यान्वयन हो रहा है और इस नीति को लेकर भारत में सरकारों, समाज और विशेषकर नयी पीढ़ी के अंदर अत्यंत उत्साह है तथा इसकी स्वीकृति तेजी से बढ़ रही है।'' उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय

अनुदान आयोग (यूजीसी) के मसौदा नियमों को सार्वजनिक कर दिया गया है जिस पर सुझाव दिए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि यूजीसी को सुधारों के लिए नियम बनाने का पूरा अधिकार है। उन्होंने कहा कि मसौदा प्रस्ताव आम जनता के सामने है और प्रत्येक राज्य को इसकी जानकारी दी गई है। उन्होंने कहा कि दस से अधिक राज्यों ने अपने सुझाव दिए हैं, साथ ही राज्य, केंद्रीय, निजी और डीम्ड विश्वविद्यालयों सहित 52 विश्वविद्यालयों ने भी अपने सुझाव दिए हैं। उन्होंने कहा कि मसौदे को सार्वजनिक कर दिया गया है और कोई भी इस संबंध में सुझाव दे सकता है।

प्रधान ने विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के चयन के बारे में कहा कि अतीत में इस पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया है। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यूजीसी के सुझाव ही किसी भी मामले में मान्य होंगे। उन्होंने गैर-शैक्षणिक व्यक्ति को कुलपति नियुक्त किए जाने के संबंध में कहा कि वर्तमान परिवेश को देखते हुए, विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ व्यक्तियों को शैक्षणिक संस्थानों का नेतृत्व करना चाहिए।

गाजा में सैन्य अभियान का विस्तार कर रहा इजराइल, हवाई हमलों में 43 फलस्तीनियों की मौत

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

दीर अल-बलाह/एपी। गाजा पट्टी में 'बड़े क्षेत्रों' पर कब्जा करने के लिए इजराइल वहां अपने सैन्य अभियान का विस्तार कर रहा है। रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने बुधवार को यह जानकारी दी।

इस बीच, गाजा पट्टी में अधिकारियों ने बताया कि इजराइल की ओर से मंगलवार को पूरी रात और बुधवार तड़के किए गए हवाई हमलों में कम से कम 43 फलस्तीनी मारे गए, जिनमें लगभग एक दर्जन बच्चे शामिल हैं।

काट्ज ने बुधवार को एक लिखित बयान में कहा कि इजराइल ''उग्रवादियों और उग्रवाद के बुनियादी ढांचे को कुचलने'' तथा ''फलस्तीनी क्षेत्र के बड़े हिस्से पर कब्जा करके उन्हें इजराइल के सुरक्षा क्षेत्रों से जोड़ने'' के लिए गाजा पट्टी में अपने सैन्य अभियान का विस्तार कर रहा है।

इजराइल सरकार ने फलस्तीनी क्षेत्र से लगी सीमा पर अपनी सुरक्षा बाड़ के उस पार गाजा में लंबे समय से एक 'बफर जोन' बनाए रखा है और 2023 में हमास के साथ युद्ध शुरू होने के बाद से उसने इसका बड़े पैमाने पर विस्तार किया है।

इजराइल का कहना है कि 'बफर जोन' उसकी सुरक्षा के लिए जरूरी है, जबकि फलस्तीनी इसे भूमि हड़पने की कवायद मानते हैं, जिससे पहले ही छोटे तटीय क्षेत्र (गाजा पट्टी) का दायरा और सिकुड़ जाता है। गाजा पट्टी की आबादी लगभग 20 लाख है।

काट्ज ने बयान में यह स्पष्ट नहीं किया कि सैन्य अभियान के विस्तार के दौरान गाजा के किन क्षेत्रों पर कब्जा किया जाएगा। उनका यह बयान तब आया, जब इजराइल ने दक्षिणी शहर राफा और आस-पास के इलाकों को पूरी तरह से खाली करने का आदेश दिया।

इजराइल गाजा में नया सुरक्षा गलियारा स्थापित करेगा : नेतन्याहू

इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बुधवार को कहा कि इजराइल गाजा में एक नया सुरक्षा गलियारा स्थापित कर रहा है। उन्होंने एक बयान में इसे मोराग गलियारा बताया। राफा और खान यूनिस के बीच स्थित एक यहूदी बस्ती के नाम पर यह गलियारा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों दक्षिणी शहरों के बीच यह गलियारा बनाया जाएगा। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने कहा है कि गाजा पट्टी में 'बड़े क्षेत्रों' पर कब्जा करने के उद्देश्य से इजराइल अपने सैन्य अभियान का विस्तार कर रहा है। नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल का लक्ष्य हमास को कुचलने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद गाजा पट्टी पर खुला, लेकिन अनिर्दिष्ट सुरक्षा नियंत्रण बनाए रखना है।

उद्घाटन

नई दिल्ली के पालम गांव के सुलभ ग्राम में डॉ. बिंदेश्वर पाठक स्मारक केंद्र के उद्घाटन के दौरान भारत के पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और अन्य।

गुजरात पटाखा गोदाम आग

मध्यप्रदेश के छह लोगों का पूरा परिवार खत्म

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बनासकांठा/भाषा। गुजरात के बनासकांठा जिले में डीसा के निकट एक अवैध पटाखा गोदाम में हुए भीषण विस्फोट में मारे गए 21 लोगों के शव लेकर उनके परिजन बुधवार सुबह मध्यप्रदेश में अपने-अपने गांवों के लिए रवाना हो गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि मृतकों में पांच बच्चे भी शामिल हैं जो मध्यप्रदेश के देवास और हरदा जिलों के संदलपुर तथा हाड़िया गांवों के रहने वाले थे।

अहमदाबाद के धोलका में एक प्लास्टिक फैक्टरी में काम करने वाले चंद्रसिंह नायक ने इस हादसे में अपनी बेटी, दामाद, नतिनी राधा (3) और नाती अभिषेक (10) के अलावा अपने दामाद के परिवार के दो अन्य सदस्यों को खो दिया। बेहद भावुक दिख रहे नायक ने बताया कि उनकी बेटी और उसके पति ने हाल ही में गोदाम में काम करना शुरू किया था, लेकिन उनकी सास पहले भी वहां काम कर चुकी थीं। उन्होंने कहा, '2मृतकों में से 10 लोग संदलपुर और 11 लोग हाड़िया के थे। '' इस हादसे में जीवित बचे राजेश नायक ने बताया कि मंगलवार सुबह करीब 9.45 बजे जब श्रमिक गोदाम पर पहुंचे तो विस्फोट हुआ।

डीसा ग्रामीण पुलिस थाने के निरीक्षक वी जी प्रजापति ने कहा, ''मृतकों के शवों को लेकर एम्बुलेंस उनके गांवों के लिए रवाना होने लगी हैं। अब तक दो-दो ताबूतों वाली दस एम्बुलेंस रवाना हो चुकी हैं।'' गुजरात के उद्योग मंत्री बलवंत सिंह राजपूत के साथ डीसा पहुंचे मध्यप्रदेश के मंत्री नागर सिंह चौहान ने कहा कि दोनों राज्यों की सरकारें पीड़ितों और उनके परिवारों को राहत प्रदान कर रही हैं। चौहान ने कहा, ''यह बहुत ही दुखद घटना है और पूरा देश पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा है....मध्यप्रदेश से लोग रोजगार की तलाश में गुजरात आते हैं और गुजरात से भी लोग रोजगार की तलाश में जाते हैं। सरकार ने इस घटना को बहुत गंभीरता से लिया है।'' गुजरात के बनासकांठा जिले में मंगलवार को एक पटाखा गोदाम में विस्फोट के बाद आग लगने और इमारत के कुछ हिस्से के ढहने की घटना में पांच बच्चों समेत 21 लोगों की मौत हो गई और छह अन्य लोग घायल हो गए। यह घटना सुबह करीब नौ बजकर 45 मिनट पर डीसा कस्बे के पास स्थित गोदाम में हुई, जहां अवैध रूप से पटाखों का भंडारण और उनका निर्माण किया जा रहा था।

ओडिशा के मुख्यमंत्री ने की स्कूलों में 'शिशु वाटिका' की शुरुआत

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

भुवनेश्वर/भाषा। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने बुधवार को नई शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के तहत राज्य के सभी स्कूलों में पांच से छह साल के बच्चों को 'प्री-स्कूल' शिक्षा देने के लिए 'शिशु वाटिका' की शुरुआत की। शिक्षा से रूबरू होने वाले नन्हे-मुन्ने बच्चों का सभी सरकारी स्कूलों में 'शिशु वाटिका' में 'प्रवेश उत्सव' या प्रवेशोत्सव के माध्यम से पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। बाद में बच्चों को 'खड़ी छुअन' (चॉक को छूना) कार्यक्रम में शामिल किया गया, जिसमें उन्होंने पहली बार स्लेट पर कुछ लिखने का प्रयास किया। शिशु-वाटिका पहल के तहत पांच-छह वर्ष की आयु के बच्चों को 'प्री-स्कूल' कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा।कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री यहां बडागडा हाई स्कूल की एक कक्षा में फर्श पर बैठे और एक बच्ची का हाथ पकड़कर उसे उसकी स्लेट पर 'शून्य' लिखने में मदद करते देखे गए। मुख्यमंत्री माझी पूर्व में शिक्षक रह चुके हैं। माझी ने बाद में कक्षा नौ और 10 के बच्चों को भोजन परोसा। राज्य ने अप्रैल 2025 से कक्षा नौ और कक्षा 10 के छात्रों के लिए मध्याह्न भोजन योजना शुरू की है। माझी ने कहा, राज्य सरकार ओडिशा के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए हमने एनईपी 2020 लागू किया है और राज्य भर के स्कूलों में शिशु वाटिका कार्यक्रम शुरू किए हैं। छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए 'प्रवेश उत्सव' और खड़ी छुअन' का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शिशु वाटिका पहल बच्चों के आधुनिक, आत्मनिर्भर और सशक्त भविष्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

सिद्दरामय्या और कांग्रेस नेतृत्व के बीच मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर चर्चा की खबर गलत : शिवकुमार

हुब्बल्ली। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार ने उनके और मुख्यमंत्री सिद्दरामय्या के नई दिल्ली दौरे के दौरान कांग्रेस नेतृत्व के साथ राज्य मंत्रिमंडल में बदलाव को लेकर चर्चा होने की अटकलों को सिरे से खारिज करते हुए इसे ''गलत सूचना'' बताया। सिद्दरामय्या बुधवार को पहले ही दिल्ली पहुंच चुके हैं, जबकि पार्टी की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष शिवकुमार के बुधवार शाम तक दिल्ली पहुंचेंगे। दोनों नेताओं की दिल्ली में होने वाले कार्यक्रमों को लेकर दी गई आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, वे पुनर्निर्मित कर्नाटक भवन बिल्डिंग-1 'कावेरी' के उद्घाटन में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री का बुधवार और बृहस्पतिवार को कुछ केंद्रीय मंत्रियों से मिलने का भी कार्यक्रम है। शिवकुमार के अनुसार, वे दिल्ली दौरे के दौरान कांग्रेस आलाकमान से भी मुलाकात करेंगे।

उपमुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर संवाददाताओं द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में कहा, किसी ने आपको इस संबंध में गलत जानकारी दी है। मंत्रिमंडल में फेरबदल मुख्यमंत्री के विवेक पर छोड़ दिया गया है। वह और आलाकमान इस पर चर्चा करेंगे और फैसला लेंगे। आपकी जानकारी सच्चाई से कोसों दूर है। उन्होंने यहां संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि विधान परिषद की चार रिक्त सीट पर पार्टी उम्मीदवारों को लेकर चर्चा होगी। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही मंत्रियों के प्रदर्शन के आधार पर मंत्रिमंडल में संभावित फेरबदल की अटकलें लगाई जा रही हैं। मंत्री पद के इच्छुक विधायकों के एक वर्ग की ओर से भी मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की मांग की जा रही है। कुछ विधायकों ने तो खुले तौर पर मंत्री बनने की इच्छा भी जताई है। सिद्दरामय्या के नेतृत्व में मई 2023 में सरकार बनने के बाद से राज्य मंत्रिमंडल में फेरबदल नहीं किया गया है।

विरोध

वामपंथी छात्र संगठनों के सदस्य बुधवार को कोलकाता में शैक्षणिक संस्थान परिसरों में छात्र सुरक्षा की मांग करते हुए एक विरोध रैली निकाली।

झंडा दिवस

मुख्यमंत्री सिद्दरामय्या ने राज्य खुफिया निदेशक हेमंत एम. निंबालकर को स्वर्ण पदक प्रदान किया, जिन्होंने राज्य में नक्सली गतिविधियों को शून्य करने के लिए विशेष सतर्कता के साथ पुलिस अभियान का नेतृत्व किया तथा सभी नक्सलियों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया। ये पदक बुधवार को सुबह बेंगलूरु के फील्ड मार्शल माणिक शाह परेड ग्राउंड में पुलिस झंडा दिवस समारोह में प्रदान किए गए।

न्यामति बैंक डकैती के मुख्य साजिशकर्ता ने टीवी धारावाहिक देखकर रची थी साजिश : कर्नाटक पुलिस

दावणगेरे। दावणगेरे के न्यामति में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) डकैती की जांच से खुलासा हुआ है कि मुख्य साजिशकर्ता ने टीवी धारावाहिक 'मनी हीस्ट' तथा बैंक चोरी और डकैती से जुड़ी फिल्में देखकर वारदात को अंजाम देने की साजिश रची थी। एसबीआई की न्यामति शाखा में 28 अक्टूबर 2024 को खिड़की की ग्रिल निकालकर घुसे अपराधियों ने 17.7 किलोग्राम सोना चोरी कर लिया था।

पुलिस ने गहन जांच के बाद तमिलनाडु और कर्नाटक के न्यामति से छह लोगों के गिरोह को गिरफ्तार किया। आरोपियों की पहचान विजय कुमार (30), उसके भाई अजय कुमार (28), अभिषेक (23), चंद्रू (23), मंजूनाथ (32) और परमानंद (30) के रूप में हुई है। मुख्य साजिशकर्ता विजय कुमार तमिलनाडु का निवासी और कई साल पहले उसने न्यामति में मिठाई की दुकान खोली थी। पुलिस ने बताया कि विजय कुमार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, इसीलिए उसने वारदात को अंजाम दिया। उसने बताया कि बैंक ने अगस्त 2023 में उसे 15 लाख रुपये का कर्ज देने से मना कर दिया था, जिसके चलते वह बैंक से खफा भी था। पुलिस ने बताया कि टीवी धारावाहिक और फिल्मों के अलावा, यूट्यूब वीडियो देखकर भी उसने वारदात की साजिश रची।

भाजपा घुसपैठ के मामले में असम पर ध्यान दे : तृणमूल सांसद सुष्मिता देव

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस की एक सदस्य ने सत्तारूढ़ भाजपा पर आरोप लगाया कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर पश्चिम बंगाल पर निशाना साधने के बजाय उसे असम पर ध्यान देना चाहिए चाहिए जहां यह एक ज्वलंत मुद्दा है। उन्होंने सरकार द्वारा लाये गये आव्रजन संबंधी एक विधेयक को संसद की स्थायी समिति के पास भेजने का सुझाव दिया। उच्च सदन में आप्रवास एवं विदेशियों विषयक विधेयक, 2025 पर हो रही चर्चा में भाग लेते हुए तृणमूल कांग्रेस की सुष्मिता देव ने दावा किया कि यह विधेयक गैर कानूनी आव्रजन, नागरिकता, निर्वासन, निरुद्ध शिविर, मतदाताओं एवं आधार कार्ड संबंधित चार कानूनों का निरसन करता है। उन्होंने कहा कि यदि इस विधेयक को संसद की स्थायी समिति के पास नहीं भेजा गया तो यह संसदीय लोकतंत्र के लिए उचित नहीं होगा।

उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष के लोग हमेशा पश्चिम बंगाल की बात करते हैं जबकि देश में यदि कोई ऐसा राज्य है जहां गैर कानूनी आव्रजन, नागरिकता, विदेशियों एवं घुसपैठियों को वापस भेजने के मुद्दे ज्वलंत हैं तो वह असम है। उन्होंने कहा कि असम में डबल इंजन की सरकार' है। तृणमूल सदस्य ने आरोप लगाया कि असम उनकी (भाजपा की) तोड़-मरोड़ वाली नीति की प्रयोगशाला है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने असम समझौते की धज्जियां उड़ायी हैं। उन्होंने कहा कि संशोधित नागरिकता कानून लागू होने के बाद अभी तक मात्र 350 लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान की गयी है। उन्होंने कहा कि सरकार के तमाम दावों के बावजूद राष्ट्रीय नागरिकता पंजी (एनआरसी) के मामले में आज तक कुछ नहीं हुआ। उन्होंने दावा किया कि सत्ता पक्ष ने 26 लाख लोगों के आधार कार्ड रोक दिए हैं। सुष्मिता ने कहा कि उनकी पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी ने मतदाता सूची के लिए कितना बड़ा आंदोलन किया था, यह जाकर पता किया जाना चाहिए। उन्होंने गृह मंत्री को चुनौती दी कि वह पहले एनआरसी को अधिसूचित करें और उसके बाद इस विषय में फिर कोई अन्य बात करें।

रील देखने की लत दिमाग ही नहीं खराब कर रही, आंखों को भी बीमार कर रही

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली। चिकित्सक पहले ही एक-दो मिनट की रील (वीडियो)देखने की लत से दिमाग पर नकारात्मक प्रभाव को लेकर चिंता जता चुके हैं लेकिन अब उन्होंने इसके आंखों पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को लेकर चेतावनी दी है। चिकित्सकों का कहना है कि बहुत अधिक समय स्क्रीन पर व्यतीत करने से विशेष तौर पर इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया मंचों पर लगातार रील देखने से सभी आयु समूहों में, खासतौर पर बच्चों और युवाओं में आंखों की समस्या में वृद्धि हो रही है। यह चेतावनी मंगलवार को दिल्ली के यशोभूमि स्थित इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर में आयोजित एशिया पैसिफिक एकेडमी ऑफ ऑप्थैल्मोलॉजी और ऑल इंडिया ऑप्थैल्मोलॉजिकल सोसाइटी की संयुक्त बैठक के दौरान प्रमुख नेत्र रोग विशेषज्ञों ने दी।

एशिया पैसिफिक एकेडमी ऑफ ऑप्थैल्मोलॉजी (एपीएओ) 2025 कांग्रेस के अध्यक्ष डॉ. ललित वर्मा ने बहुत अधिक समय स्क्रीन देखने पर व्यय करने के कारण होने वाली साइलेंट एपिडेमिक ऑफ डिजिटल आई स्ट्रेन' (डिजिटल उपकरणों के इस्तेमाल से खामोशी से बढ़ती आंखों की बीमारी की महामारी) के खिलाफ कड़ी चेतावनी जारी की। उन्होंने कहा, हम आंखों में खुश्की, निकट दृष्टि दोष, आंखों में दबाव और यहां तक कि शुरुआती दौर में ही भेंगापन के मामलों में तीव्र वृद्धि देख रहे हैं, खासकर उन बच्चों में जो घंटों रील देखते रहते हैं।

डॉ.वर्मा ने कहा, हाल ही में एक छात्र लगातार आंखों में जलन और धुंधली दृष्टि की शिकायत लेकर हमारे पास आया था। जांच के बाद, हमने पाया कि घर पर लंबे समय तक स्क्रीन पर रील देखने के कारण उसकी आंखों में पर्याप्त नमी नहीं बन रही थी। उसकी आंखों में तुरंत दवा डाली गईं और 20-20-20 नियम का पालन करने की सलाह दी गई - यानि के हर 20 मिनट में 20 सेकेंड का ब्रेक लेकर 20 फुट दूर किसी चीज को देखने को कहा गया। आयोजन समिति के अध्यक्ष और ऑल इंडिया ऑप्थैल्मोलॉजिकल सोसाइटी के अध्यक्ष डॉ. हरबंस लाल ने मुद्दे की गंभीरता को समझाया। उन्होंने कहा कि छोटी, आकर्षक रीलें लंबे समय तक ध्यान

खींचने और उसे बनाए रखने के लिए डिजाइन की गई हैं।

डॉ.लाल ने कहा, ''लगातार स्क्रीन पर ध्यान केंद्रित करने से पलकें झपकने की दर 50 प्रतिशत कम हो जाती है, जिससे ड्राई-आई सिंड्रोम और एकोमोडेशन स्पाज्म (निकट और दूर की वस्तुओं के बीच फोकस बदलने में कठिनाई) की समस्या उत्पन्न होती है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यदि इस आदत पर नियंत्रण नहीं किया गया, तो इससे दीर्घकालिक दृष्टि संबंधी समस्याएं और यहां तक कि आंखों में स्थायी परेशानी भी हो सकती है।'' डॉ. लाल ने आगे बताया कि जो बच्चे प्रतिदिन घंटों टीवी देखते हैं, उनमें प्रारंभिक निकट दृष्टि समस्या होने का खतरा होता है, जो पहले से कहीं अधिक तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि वयस्कों को भी नीली रोशनी के कारण अक्सर सिरदर्द, माइग्रेन और नींद संबंधी विकार का सामना करना पड़ रहा है। डॉ.लाल ने कहा कि हाल के अध्ययनों के अनुसार, 2050 तक विश्व की 50 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या निकट दृष्टिदोष से ग्रस्त होगी, जो अपरिवर्तनीय अंधेपन का सबसे आम कारण है। डॉ. लाल ने कहा कि अब स्क्रीन पर बिताए जाने वाले समय में वृद्धि के कारण, हम 30 वर्ष की आयु तक चश्मे के नंबर में उतार-चढ़ाव देख रहे हैं, जो कुछ दशक पहले 21 वर्ष तक देखा जाता था।

अध्ययनों के मुताबिक ऐसे लोगों की तादाद बढ़ रही है, विशेष रूप से छात्र और कामकाजी पेशेवर की जो उच्च गति, दृश्य उत्तेजक सामग्री के लंबे समय तक संपर्क के कारण आंखों में परेशानी, भेंगापन और बिगड़ती दृष्टि से जूझ रहे हैं। चिकित्सकों ने लगातार रील देखने से सामाजिक अलगाव, मानसिक थकान और संज्ञानात्मक अधिभार' (जरूरत से अधिक सूचना का संग्रह) की चिंताजनक प्रवृत्ति पर भी ध्यान दिलाया है। एआईओएस के अध्यक्ष और वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. समर बसाक ने अत्यधिक स्क्रीन समय के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव को रेखांकित किया। उन्होंने कहा, हम एक ऐसी चिंताजनक प्रवृत्ति देख रहे हैं, जहां लोग रील में इतने खो जाते हैं कि वे वास्तविक दुनिया के संबंधों की उपेक्षा कर देते हैं, जिसके परिणामस्वरूप पारिवारिक रिश्ते खराब हो जाते हैं और शिक्षा और काम पर ध्यान कम हो जाता है।

वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ और एआईओएस के भावी अध्यक्ष डॉ. पार्थ बिस्वास ने कहा, कृत्रिम प्रकाश, दृश्य में तीव्र परिवर्तन और लंबे समय तक आंखों के करीब की गतिविधि का संयोजन आंखों को अत्यधिक उत्तेजित कर रहा है, जिसके कारण एक ऐसी घटना हो रही है जिसे हम रील 'विजन सिंड्रोम' कहते हैं। इससे पहले कि यह एक पूर्ण जन स्वास्थ्य संकट बन जाए, हमें इसे गंभीरता से लेना चाहिए। नेत्र रोग विशेषज्ञों ने अत्यधिक रील देखने के प्रतिकूल प्रभावों से निपटने के लिए 20-20-20 नियम का पालन करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि पलकों को झपकाने की दर बढ़ाएं, स्क्रीन देखते समय अधिक बार पलक झपकाने का सचेत प्रयास करें, स्क्रीन देखने का समय कम करें और नियमित रूप से स्क्रीन से विराम लें क्योंकि इससे दीर्घकालिक नुकसान को रोकने में मदद मिल सकती है।

आरडब्ल्यूएफ ने उत्पादन में रचा नया रिकार्ड

बेंगलूरु। शहर के यलहंका स्थित रेल व्हील फैक्ट्री (आरडब्ल्यूएफ) जो कि कास्ट व्हील, फोर्ज्ड एक्सल और व्हीलसेट के निर्माण में कार्यरत है ने पिछले वित्तीय वर्ष में सबसे ज़्यादा 2,01,150 व्हीलों का निर्माण और कुल 98,350 व्हीलसेट का अब तक का सबसे ज़्यादा निर्माण कर अपने आप में नया रिकार्ड बनाया है। आरडब्ल्यूएफ ने 93,880 एक्सल का निर्माण कर दूसरा सबसे ज़्यादा निर्माण हासिल किया। संस्थान ने एक अतिरिक्त एक्सल मशीनिंग लाइन चालू करके अपनी उत्पादन क्षमता को भी बढ़ाया है जिससे वार्षिक उत्पादन क्षमता में 42,500 एक्सल की वृद्धि होगी। आरडब्ल्यूएफ एक ऊर्जा

गहन संयंत्र है, इसलिए ऊर्जा संरक्षण के लिए भी कई अभिनव उपाय शुरू किए गए हैं। आरडब्ल्यूएफ ने कारखाने में सुरक्षित काम करने के लिए सभी क्षेत्रों में चौबीसों घंटे उचित रोशनी की की आपूर्ति हेतु शॉप फ्लोर में रोशनी बढ़ाने के लिए पाइप्ड डे लाइटिंग सिस्टम लगाने की संभावना तलाशने का फैसला किया गया। आरडब्ल्यूएफ ने थर्मल सैंड रिक्लेमेशन प्लांट ने फाउंड्री सैंड की रिकवरी को सक्षम बनाया है ताकि पर्यावरणीय प्रभाव कम हो सके। हीट ट्रीटमेंट फर्नेस जैसे भारी हीटिंग उपकरण पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) पर चलते हैं जो जीवाश्म ईंधन से ऊर्जा के अन्य स्रोतों की तुलना में कम कार्बन गहन है। आरडब्ल्यूएफ ने एक आर्द्रभूमि बनाई है जिसमें वर्षा जल का संचयन किया जाता है और निचले इलाकों में एकत्र किया जाता है।

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा बुधवार को नाडुर में सह-जिला आयुक्त के कार्यालय भवन के शिलान्यास समारोह के दौरान।

तमिलनाडु विधानसभा ने कच्चातीवु द्वीप को वापस लेने की मांग करते हुए प्रस्ताव पारित किया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। तमिलनाडु विधानसभा ने बुधवार को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें केंद्र से अनुरोध किया गया कि वह राज्य के मछुआरों के मछली पकड़ने के पारंपरिक अधिकारों की रक्षा के लिए स्थायी समाधान के रूप में कच्चातीवु द्वीप को वापस ले। यह द्वीप श्रीलंका को सौंप दिया गया था। प्रस्ताव पेश करते हुए मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने कहा कि कुछ राजनीतिक दलों की यह आदत बन गई है कि वे यह गलत सूचना फैलाते हैं कि यह राज्य सरकार थी जिसने कच्चातीवु को श्रीलंका को सौंप दिया। उन्होंने कहा, यहां तक कि केंद्र सरकार भी वही गलती कर रही है। यह दुर्भाग्यपूर्ण एवं अस्वीकार्य है। स्टालिन ने कहा कि जहां तक कच्चातीवु का सवाल है, तो तत्कालीन मुख्यमंत्री एम करुणानिधि ने इसे सौंपे जाने का कड़ा विरोध किया था और द्रमुक सांसदों ने भी इस पर आपत्ति जताई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 28 जून 19%4 को कच्चातीवु समझौते पर हस्ताक्षर होने के एक दिन बाद कलैगनार (करुणानिधि) ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी और इसकी निंदा करते हुए प्रस्ताव पारित किया था। स्टालिन ने कहा कि उसी दिन उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर भारत–श्रीलंका समझौते पर 'गहरी निराशा' व्यक्त की थी। उन्होंने बताया कि इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता ने तीन अक्टूबर, 1991 और तीन मई, 2013 को तथा ओ पन्नीरसेल्वम ने भी अपने कार्यकाल के दौरान पांच मई, 2014 को विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर कच्चातीवु को पुनः प्राप्त करने के लिए कदम उठाने की मांग की थी।

स्टालिन ने कहा कि 2021 में मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने न केवल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर द्वीप को वापस लेने का दबाव बनाया, बल्कि मछुआरों की समस्याओं का स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के लिए कई मौकों पर पत्र भी लिखे। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा 27 मार्च को राज्यसभा में पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार, श्रीलंकाई नौसेना द्वारा प्रतिदिन औसतन दो मछुआरों को गिरफ्तार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के अनुसार, जयशंकर ने 27 मार्च को राज्यसभा में बताया कि 97 भारतीय मछुआरे श्रीलंका की जेल में हैं। उन्होंने कहा, पिछले साल ही श्रीलंकाई नौसेना ने करीब 530 मछुआरों को पकड़ा था।स्टालिन द्वारा पेश किए गए इस प्रस्ताव को गहन चर्चा के बाद विधानसभा में पारित कर दिया गया।

भाजपा सदस्य वनथी श्रीनिवासन ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय से कच्चातीवु पर भाजपा के रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी प्रस्ताव का समर्थन करती है, लेकिन जानना चाहती है कि जब द्रमुक ने दस साल तक कांग्रेस के नेतृत्व वाली संप्रग सरकार के साथ सत्ता साझा की थी, तो उसने द्वीप को वापस पाने का अवसर क्यों गंवा दिया। उन्होंने यह भी दावा किया कि तत्कालीन मुख्यमंत्री एम करुणानिधि को (द्वीप को श्रीलंका को सौंपे जाने के) घटनाक्रम की जानकारी थी। इस पर सदन के नेता दुरईमुरुगन ने कहा कि करुणानिधि ने द्वीप को सौंपे जाने का कड़ा विरोध किया था।

कानून मंत्री एस रघुपति ने कहा, ''इस मुद्दे पर न तो केंद्र ने कलैगनार से सलाह ली और न ही उन्होंने अपनी सहमति दी।'' कांग्रेस नेता के सेल्वापेरुन्थगई ने दावा किया कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के योगदान को छिपाया जा रहा है। उन्होंने कहा, हालांकि कच्चातीवु की केवल 285 एकड़ जमीन लंका को दी गई, लेकिन उन्होंने 'वेज बैंक' का 4,600 वर्ग किलोमीटर हिस्सा भारत को दिलवा दिया।

विपक्ष के नेता एडप्पाडी के. पलानीस्वामी ने संप्रग शासन में एक दशक तक सत्ता में रहने के बावजूद इस विषय पर बहुत कम काम करने के लिए द्रमुक की आलोचना की। हालांकि उन्होंने प्रस्ताव का समर्थन किया। मुख्य विपक्षी दल अखिल भारतीय अन्नाद्रमुक मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) ने समर्थन दिया। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और कांग्रेस ने भी इसका समर्थन किया। प्रस्ताव में कहा गया है, कच्चातीवु द्वीप को वापस लेना तमिलनाडु के मछुआरों के मछली पकड़ने के पारंपरिक अधिकारों की रक्षा करने और श्रीलंकाई नौसेना के कारण उन्हें होने वाली परेशानियों को कम करने का एकमात्र स्थायी समाधान है। इसमें कहा गया, उपर्युक्त बातों पर विचार करते हुए यह सम्मानित सदन सर्वसम्मति से केंद्र सरकार से आग्रह करता है कि वह भारत–श्रीलंका समझौते की तत्काल समीक्षा करे और कच्चातीवु द्वीप को वापस पाने के लिए सभी कदम उठाए। सदन भारत के माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह करता है कि वह श्रीलंका की अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान सद्भावना के आधार पर हमारे सभी बंदी मछुआरों को रिहा कराने तथा उनकी जब्त नौकाओं को वापस कराने के लिए श्रीलंका सरकार से बातचीत करें। भारत ने 1974 और 1976 में समझौतों के माध्यम से कच्चातीवु द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया था।

स्टालिन ने 'निष्पक्ष परिसीमन' की मांग को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का समय मांगा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने प्रस्तावित परिसीमन संबंधी चिंताओं पर एक ज्ञापन सौंपने के लिए बुधवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात का समय देने का अपना अनुरोध एक बार फिर से दोहराया। स्टालिन ने प्रधानमंत्री मोदी को कुछ दिन पहले किए गए अपने अनुरोध की याद दिलाई जिसमें उन्होंने विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसदों के साथ उनसे मिलने का समय मांगा था, ताकि वह प्रस्तावित परिसीमन से संबंधित चिंताओं पर उन्हें एक ज्ञापन सौंप सकें।

स्टालिन ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''जैसा कि पहले बताया गया है, हम अपने लोगों के लिए इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपना एकजुट रुख बताने के लिए आपका समय चाहते हैं। आपकी शीघ्र प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है।'' मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक आधिकारिक पत्र भी पोस्ट किया, जो उन्होंने 27 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री को लिखा था। पत्र में स्टालिन ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री से बातचीत करने का अनुरोध किया था। स्टालिन ने अपने पत्र में कहा, ''22 मार्च, 2025 को चेन्नई में निष्पक्ष परिसीमन पर संयुक्त कार्रवाई समिति की पहली बैठक आयोजित की गई, जो एक ऐतिहासिक बैठक थी जिसमें देश भर से विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करने वाले मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और प्रमुख नेता एक साथ आए।''

द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के अध्यक्ष ने कहा, ''हमारे विचार–विमर्श से उभरने वाली आवाजें राजनीतिक सीमाओं से परे हैं और इनमें विविध क्षेत्रों के नागरिकों की चिंताएं शामिल हैं, जो हमारे संसदीय लोकतंत्र में निष्पक्ष प्रतिनिधित्व चाहते हैं। चूंकि, यह मुद्दा हमारे राज्यों और नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए संयुक्त कार्रवाई समिति की ओर से औपचारिक रूप से ज्ञापन प्रस्तुत करने के लिए मैं आपसे मुलाकात का अनुरोध करता हूं।''

स्टालिन ने प्रधानमंत्री मोदी से वक्फ संशोधन विधेयक वापस लेने का आग्रह किया

चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 को वापस लेने की मांग की। उन्होंने दावा किया कि इस विधेयक से मुसलमानों के हितों को नुकसान पहुंचेगा। स्टालिन ने कहा कि संविधान प्रत्येक नागरिक को अपने–अपने धर्म के पालन करने का अधिकार देता है और इसे (अधिकार को) बनाए रखना तथा उसकी रक्षा करना निर्वाचित सरकारों का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि वक्फ अधिनियम, 1995 में प्रस्तावित संशोधनों में अल्पसंख्यकों को दी गई संवैधानिक सुरक्षा को ध्यान में नहीं रखा गया है और इससे मुस्लिम समुदाय के हितों को गंभीर नुकसान पहुंचेगा। मुख्यमंत्री पहले ही वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध कर चुके हैं। उन्होंने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री से व्यक्तिगत हस्तक्षेप की मांग की और रेखांकित किया कि कुछ दिन पहले तमिलनाडु विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से विधेयक वापस लेने का आग्रह किया था। स्टालिन ने कहा कि मौजूदा वक्फ अधिनियम के प्रावधान समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं और वे वक्फ की संपत्तियों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। उन्होंने दावा किया कि वक्फ अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और संरक्षण में वक्फ बोर्डों की शक्तियों और जिम्मेदारियों को कमजोर कर देंगे। मुख्यमंत्री ने यह दावा भी किया कि मौजूदा अधिनियम में बड़े पैमाने पर प्रस्तावित संशोधन इसकी मूल भावना को कमजोर करेंगे।

आरएसएस नेता की हत्या के मामले में आरोपी पीएफआई के 10 सदस्यों को जमानत

कोच्चि/भाषा। केरल उच्च न्यायालय ने पलक्कड़ जिले में तीन वर्ष पहले की गई राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) नेता श्रीनिवासन की हत्या के मामले में आरोपी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के 10 सदस्यों को बुधवार को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति राजा विजयराघवन और न्यायमूर्ति पी.वी. बालकृष्णन की पीठ ने शफीक, जफर बी, नासर, जमशीर एच, अब्दुल बसिथ, मोहम्मद शफीक के, अशरफ के, जिशाद बी, अशरफ मौलवी और सिराजुद्दीन को राहत दी। इस मामले में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) विशेष अदालत द्वारा जमानत देने से इनकार करने के बाद इन सभी ने इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख किया था। विस्तृत आदेश फिलहाल उपलब्ध नहीं है। उच्च न्यायालय ने पिछले साल मामले में आरोपी पीएफआई के 17 अन्य सदस्यों को जमानत दी थी। शुरुआत में श्रीनिवासन की हत्या के सिलसिले में 51 लोगों को आरोपी बनाया गया था। गिरफ्तार किए गए लोगों में से एक की मौत हो गई और सात फरार आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। शेष के खिलाफ जुलाई और दिसंबर 2022 में दो चरणों में आरोपपत्र दाखिल किए गए। दिसंबर 2022 में केंद्र ने आरोपियों के खिलाफ हत्या के मामले की जांच करने का निर्देश दिया था। आरएसएस के पूर्व जिला नेता एवं पदाधिकारी एस.के. श्रीनिवासन पर 16 अप्रैल 2022 को पलक्कड़ के मेलामुरी में छह लोगों ने हमला कर दिया था जब वह अपनी मोटरसाइकिल की दुकान पर थे।

तमिलनाडु ई-पास प्रणाली :

ऊटी में व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद, ऑटो और टैक्सी सड़कों से नदारद

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

उदगमंडलम। तमिलनाडु के नीलगिरि जिले में बुधवार को व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे और ऑटो तथा पर्यटक टैक्सियां सड़कों पर नजर नहीं आयीं। वाहनों की आवाजाही पर नियंत्रण रखने के लिए अदालत के फैसले के अनुरूप लागू की गई ई–पास प्रणाली के विरोध में वाहन सड़कों से नदारद रहे। इस आंदोलन से पर्यटक बुरी तरह प्रभावित हुए, जिन्होंने होटल में उपलब्ध कमरों और भोजन के लिए काफी अधिक कीमतों के वसूले जाने की शिकायत की।

ई–पास प्रणाली के पूर्ण विरोध के कारण पर्यटक प्रमुख रूप से प्रभावित हुए, क्योंकि होटल बंद रहने के कारण उन्हें होटल के कमरे और भोजन उपलब्ध नहीं हो सका। प्रदर्शन के कारण क्षेत्र में होटल और रेस्तरां बंद रहे। लोग सरकारी अम्मा कैंटीनों में कतारों में खड़े दिखे, जबकि सड़क किनारे विभिन्न स्थानों पर खाद्य सामग्री बेचने वाले विक्रेता खड़े हुए थे। अम्मा कैंटीन का नाम दिवंगत मुख्यमंत्री जे जयललिता के नाम पर रखा गया है और इन दुकानों पर रियायती दरों पर भोजन उपलब्ध कराया जाता है।

केरल के एक मौलाना ने कहा कि भोजन बहुत अधिक कीमत पर बेचा जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि जिस होटल ने मंगलवार तक उन्हें 5,000 रुपये में कमरा किराए पर दिया था, वह अब 15,000 रुपये मांग रहा है। उन्होंने होटल के किराए पर नियंत्रण रखने के लिए एक तंत्र की मांग की। स्थानीय निवासी राजेश ने भोजन और होटल के कमरों की बढ़ी हुई दरों की ओर भी ध्यान दिलाया, साथ ही उन्होंने कहा कि ई–पास प्रणाली से छुट्टियों के मौसम के दौरान पहाड़ी जिले में व्यापार प्रभावित होगा।

स्थानीय चाय किसान संघ के सचिव सुकुमारन ने ई–पास पहल का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इससे वाहनों की आवाजाही सुचारू रूप से चलाने में मदद मिलेगी और भीड़–भाड़ से बचा जा सकेगा। नीलगिरि जिले के उदगमंडलम (ऊटी), कोटागिरी, गुडालुर और पंडालुर में दुकानें बंद रहीं। प्रदर्शनकारी दुकानदारों के अलावा पर्यटक एवं टैक्सी संचालक ई–पास प्रणाली को वापस लेने की मांग कर रहे हैं और उनका कहना है कि इससे उनकी आजीविका प्रभावित हो रही है।

नए आदेश के अनुसार, निजी वाहनों से जिले में आने वाले लोगों को पहले सरकारी पोर्टल पर आवेदन करना होगा और ई–पास प्राप्त करना होगा। मद्रास उच्च न्यायालय ने इससे पहले तमिलनाडु के ऊटी और कोडईकनाल (डिंडीगुल) के लिए ई–पास प्रणाली को अनिवार्य कर दिया था, ताकि गर्मियों के दौरान पहाड़ी पर्यटन आकर्षण केंद्रों में वाहनों की बढ़ती संख्या पर रोक लगाई जा सके।

एक अप्रैल से लागू हुई इस व्यवस्था के अनुसार, नीलगिरि में प्रवेश करने वाले वाहनों की संख्या सप्ताह के दिनों में 6,000 तथा सप्ताहांत में 8,000 तक सीमित रहेगी।

अशोक लेलैंड ने वाहन वित्तपोषण के लिए नागालैंड ग्रामीण बैंक के साथ की साझेदारी

चेन्नई/नई दिल्ली। वाणिज्यिक वाहन विनिर्माता कंपनी अशोक लेलैंड ने अपने ग्राहकों को वाहन वित्तपोषण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नागालैंड ग्रामीण बैंक के साथ साझेदारी की बुधवार को जानकारी दी। कंपनी ने बयान में कहा, दोनों कंपनियों ने एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। यह अशोक लेलैंड और नागालैंड ग्रामीण बैंक दोनों को ग्राहकों को अनुकूलित वित्तीय समाधान प्रदान करने में सक्षम बनाएगा। अशोक लेलैंड के मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) बालाजी के. एम. ने कहा, ''नागालैंड ग्रामीण बैंक एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है जिसकी राज्य में मजबूत उपस्थिति है। इस साझेदारी के साथ, क्षेत्र में हमारे ग्राहकों को विशेष रूप से तैयार आसान पुनर्भुगतान योजनाओं के साथ व्यापक वित्तपोषण समाधान तक पहुंच प्राप्त होगी।''

कांग्रेस वक्फ संपत्ति पर अतिक्रमण को छिपाने के लिए संशोधन का विरोध कर रही है : बोम्मई

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु/नई दिल्ली। पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद बसवराज बोम्मई ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी, जिसने देश भर में वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण किया है, अपने अतिक्रमण को छिपाने के लिए वक्फ अधिनियम में संशोधन का विरोध कर रही है। बुधवार को नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वक्फ विधेयक 1950 के दशक में पेश किया गया था और 1990 और 2013 में इसमें संशोधन किया गया था। मौजूदा संशोधन कोई नई बात नहीं है। 2013 से पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री के. रहमान खान की अगुवाई वाली समिति ने कई सिफारिशें की थीं। तत्कालीन यूपीए सरकार ने उनमें से कुछ ही सिफारिशों को लागू किया और बाकी को छोड़ दिया।

सांसद ने कहा कि देश का कानूनी ढांचा बहुत बड़ा है और संविधान सर्वोच्च है। हालांकि, 1990 और 2013 में किए गए संशोधनों ने वक्फ को सभी कानूनों से ऊपर रखा, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप को भी रोक दिया। मौजूदा संशोधन का उद्देश्य इस स्थिति को सुधारना है।

बोम्मई ने बताया कि वक्फ संपत्तियों को लेकर कई कानूनी विवाद हैं। मुस्लिमों के स्वामित्व वाली संपत्तियों को वक्फ को सौंप दिया गया है और कर्नाटक में कई वक्फ संपत्तियां कांग्रेस नेताओं के नियंत्रण में आ गई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने एक बड़ी रिपोर्ट का हवाला दिया, जो कथित तौर पर इस मुद्दे को उजागर करती है और दावा करती है कि 1,500 साल से अधिक पुराने इतिहास वाले मंदिरों को भी वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया है और कुछ सरकारी स्वामित्व वाली संपत्तियों को वक्फ संपत्ति के रूप में नामित किया गया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अन्य सभी समुदायों के लिए राजस्व अधिनियम सर्वोच्च माना जाता है, लेकिन इसे वक्फ संपत्तियों पर लागू नहीं किया गया है। राजस्व अधिनियम सभी के लिए सर्वोच्च कानून होना चाहिए और संयुक्त संसदीय समिति ने व्यापक चर्चा की है और देश भर में जनता की राय मांगी है। मुस्लिम, ईसाई और अजमेर दरगाह प्रशासन सहित कई समुदायों ने प्रस्तावित संशोधनों का स्वागत किया है। उन्होंने वादा किया कि निर्विवाद वक्फ संपत्तियां वक्फ संपत्ति बनी रहेंगी और संशोधन देश के कानूनी ढांचे के अनुसार किए गए हैं। सांसद ने अपना आरोप दोहराया कि कांग्रेस ने देशभर में वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण किया है और अब अपनी गलतियों को छिपाने के लिए संशोधनों का विरोध कर रही है। मुस्लिम बोर्ड में हिंदुओं को शामिल करने पर कांग्रेस की आपत्ति के बारे में बोम्मई ने कहा कि तटीय क्षेत्र में मुजराई विभाग के तहत कई मंदिरों में मुस्लिम प्रशासक हैं।

'कझकम' के कर्मचारियों ने 'जातिगत भेदभाव' के आरोपों के बीच इस्तीफा दिया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

त्रिशूर (केरल)/भाषा। त्रिशूर के प्रसिद्ध कूडलमाणिक्यम मंदिर के एक 'कझकम' कर्मचारी ने जातिगत भेदभाव के आरोपों के बाद व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों ने बुधवार को बताया कि बालू को राज्य द्वारा संचालित देवस्वओम भर्ती बोर्ड द्वारा 'कझकम' कार्य के लिए नियुक्त किया गया था। बालू ने मंगलवार शाम को देवस्वओम प्रशासक को अपना इस्तीफा सौंपा। 'कझकम' मंदिर में वरिष्ठताक्रम के अनुसार एक विशेष समूह होता है जिसे माला तैयार करने और अन्य औपचारिक कार्य सौंपा जाता है।

मंदिर की नौकरी से एझावा समुदाय के व्यक्ति के इस्तीफे ने एक बार फिर राज्य में खासकर मंदिरों में मौजूद कथित जातिगत भेदभाव के मुद्दे को सामने ला दिया है। इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए देवस्वओम मंत्री वी. एन. वासवन ने कहा कि बालू को सभी निर्धारित नियमों और मानदंडों के अनुसार भर्ती किया गया था। उन्होंने मदुरै में मीडियाकर्मियों से कहा, सरकार चाहती है कि वह (बालू) अपने पद पर बने रहें। हमने बालू को पहले ही सूचित कर दिया है कि सरकार उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करेगी। लेकिन, उन्होंने मंगलवार को अपना इस्तीफा दे दिया। मंत्री के अनुसार, बालू ने 'कझकम' कर्तव्यों से लिपिक पद पर स्थानांतरित होने पर काम जारी रखने की इच्छा व्यक्त की है। विवादों के बाद छुट्टी पर गए कर्मचारी ने अपने त्यागपत्र में नौकरी छोड़ने के लिए व्यक्तिगत और स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है।

मंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि जब भी बालू कझकम पद पर आना चाहेंगे, सरकार उन्हें अवसर प्रदान करेगी। देवस्वओम भर्ती बोर्ड के एक अधिकारी ने स्पष्ट किया कि इस्तीफा व्यक्तिगत निर्णय है और बोर्ड का इससे कोई लेना–देना नहीं है। देवस्वओम भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष के. बी. मोहनदास ने इस मुद्दे पर मंदिर के तंत्रियों द्वारा अपनाए गए रुख की आलोचना की और कहा कि यह सभ्य समाज के लिए उचित नहीं है।

हाल में बालू मंदिर में 'कझकम' के कर्तव्यों को संभालने के लिए आए थे, लेकिन 'तंत्रियों' (मुख्य पुजारियों) ने देवस्वओम बोर्ड के पास शिकायत दर्ज कराई, जिसमें कथित तौर पर कहा गया कि अगर उन्हें काम करने की अनुमति दी गई तो वे अपनी ज़िम्मेदारियों को नहीं निभाएंगे। इसके बाद, बोर्ड के अधिकारियों ने उन्हें अस्थायी रूप से कार्यालय कर्तव्यों में फिर से नियुक्त किया।

हालांकि, राज्य सरकार ने इस पर आपत्ति जताई थी और यह स्पष्ट किया था कि मौजूदा अधिनियमों और नियमों के अनुसार नियुक्त पिछड़े समुदाय के व्यक्ति को मंदिर में काम करने की अनुमति दी जानी चाहिए। सरकारी सूत्रों के अनुसार, मंदिर में 'कझकम' के दो पद हैं – एक 'तंत्रियों' द्वारा नियुक्त किया जाता है और दूसरा अधिनियमों और नियमों के अनुसार भरा जाता है। इरिनजालाकुडा में स्थित प्राचीन मंदिर भगवान राम के तीसरे भाई भगवान भरत को समर्पित केरल के कुछ मंदिरों में से एक है।

तमिलनाडु से राजस्थान के लिए विशेष ट्रेन सेवाएं

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। दक्षिण रेलवे से प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार ग्रीष्म ऋतु के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को कम करने के लिए तमिलनाडु से राजस्थान के लिए विशेष ट्रेन चला रहा है। राजस्थान जाने वाले यात्रियों को ट्रेनों में आरक्षित सीट नहीं मिल पा रही है। जिसके कारण उन्हें काफी परेशानी उठाकर गंतव्य तक जाना पड़ रहा है। इन ट्रेनों की सेवाओं की घोषणा से राजस्थान प्रवासियों में खुशी की लहर है।

डॉ एमजीआर चेन्नई सेंट्रल-भगत की कोठी-डॉ एमजीआर चेन्नई सेंट्रल साप्ताहिक स्पेशल :

ट्रेन संख्या 06157 डॉ एमजीआर चेन्नई सेंट्रल–भगत की कोठी साप्ताहिक स्पेशल की 13 सेवाएं 9 अप्रैल से 2 जुलाई तक प्रत्येक बुधवार को डॉ एमजीआर चेन्नई सेंट्रल से 19.45 बजे रवाना होगी और तीसरे दिन 12.30 बजे भगत की कोठी पहुंचेगी। वापसी दिशा में ट्रेन संख्या 06158 भगत की कोठी–डॉ एमजीआर चेन्नई सेंट्रल साप्ताहिक स्पेशल की 13 सेवाएं 12 अप्रैल से 5 जुलाई तक प्रत्येक शनिवार को भगत की कोठी से 05.30 बजे रवाना होगी और अगले दिन 23.15 बजे डॉ एमजीआर चेन्नई सेंट्रल पहुंचेगी। इस ट्रेन में 1–एसी टू टियर कोच, 2–एसी थ्री टियर कोच, 12–स्लीपर क्लास कोच, 4–सामान्य द्वितीय श्रेणी कोच और 2–द्वितीय श्रेणी कोच (दिव्यांगजन अनुकूल)। यह ट्रेन डॉ. एमजीआर चेन्नई सेंट्रल से रवाना होकर सुलुरुपेटा, गुडुर, नेल्लोर, ओंगोल, विजयवाड़ा, खम्मम, वारंगल, बल्हारशाह, चंद्रपुर, वर्धा, धानमंडल, बडनेरा, अकोला, मल्कापुर, भुसावल, जलगांव, नंदुरबार, उधना, अंकलेश्वर, बड़ौदा, आनंद, साबरमती बीजी, महसेना, पाटन, भीलड़ी जं, रानीवाड़ा, मारवाड़ भीनमाल, मोद्रन, जालोर, मोकलसर, समदड़ी जं., लूनी, स्टेशनों पर रुकते हुए भगत की कोठी पहुंचेगी।

कोयंबटूर-भगत की कोठी-कोयंबटूर साप्ताहिक स्पेशल :

ट्रेन संख्या 06181 कोयंबटूर–भगत की कोठी साप्ताहिक स्पेशल की 13 सेवाएं 10 अप्रैल से 3 जुलाई तक प्रत्येक गुरुवार को कोयंबटूर से 02.30 बजे रवाना होगी और तीसरे दिन 11.30 बजे भगत की कोठी पहुँचेगी। वापसी दिशा में ट्रेन संख्या 06182 भगत की कोठी–कोयंबटूर साप्ताहिक स्पेशल की 13 सेवाएं 23.00 बजे भगत की कोठी से रवाना होगी 13 अप्रैल से 06 जुलाई तक रविवार को चलेगी और चौथे दिन 09.30 बजे कोयंबटूर पहुंचेगी। इस ट्रेन में 4 – एसी थ्री टियर कोच, 7– एसी थ्री टियर इकॉनमी कोच, 1– स्लीपर क्लास कोच, 4– जनरल सेकंड क्लास कोच और 2– लगेज कम ब्रेक वैन होंगे। यह ट्रेन कोयंबटूर से रवाना होकर तिरुपुर, इरोड, सेलम, जोलारपेट्टई, काटपाडी, रेनिगुंटा, कडप्पा, येरागुंटला, गुत्ती, धोने, कुरनूल शहर, महबूबनगर, काचीगुडा, करमारेड्डी, निजामाबाद, मुदखेड़, हजूर साहिब नांदेड़, पूर्णा, हिंगोली, वाशिम, अकोला, भुसावल, जलगांव, नंदुरबार, सूरत, बड़ौदा, साबरमती बीजी, भीलड़ी जं, रानीवाड़ा, मारवाड़ भीनमाल, मोद्रन, जालोर, मोकलसर, समदड़ी जं. स्टेशनों पर रुकते हुए भगत की कोठी पहुंचेगी।

इरोड-बाड़मेर साप्ताहिक स्पेशल :

ट्रेन नंबर 06097 इरोड–बाड़मेर साप्ताहिक स्पेशल 08 अप्रैल से 10 जून तक इसकी 10 सेवाएं प्रत्येक मंगलवार को इरोड से 06.20 बजे रवाना होगी और तीसरे दिन 04.30 बजे बाड़मेर पहुंचेगी। वापसी दिशा में ट्रेन नंबर 06098 बाड़मेर–इरोड साप्ताहिक स्पेशल कर 10 फेरे 11 अप्रैल से 13 जून तक शुक्रवार को 22.50 बजे बाड़मेर से रवाना होगी और तीसरे दिन 20.15 बजे इरोड पहुंचेगी। इस ट्रेन में 2– एसी थ्री टियर कोच, 14– स्लीपर क्लास कोच, 4– सामान्य द्वितीय श्रेणी कोच और 2– द्वितीय श्रेणी कोच (दिव्यांगजन अनुकूल)। इरोड से यह ट्रेन तिरुपूर, पोदनूर, पलक्कड़, शोरानूर, तिरूर, कोझिकोड, कन्नूर, कासरगोड, मंगलूरु जं, उधना, कुन्दापुरा, बिंदूर मूकाम्बिका रोड, भटकल, मुर्देश्वर, कुमटा, गोकर्ण रोड, अंकोला, कारवार, मडगांव, करमाली, थिविम, सावंतवाड़ी रोड, कुदाल, कांकावली, विभववादी रोड, राजापुर रोड, रत्नागिरि, संगमेश्वर रोड, चिपलुन, खेड़, मानगोआं, रोहा, पनवेल, वसई रोड, पालघर, वापी, सूरत, भरूच, वडोदरा, नडियाद जं, साबरमती बी.जी, भीलड़ी जं, रानीवाड़ा, मारवाड़ भीनमाल, मोद्रन, जालोर, मोकलसर, समदड़ी, बालोतरा, बायतु होते हुए बाड़मेर पहुंचेगी

राजस्थान फार्मर रजिस्ट्री में देश में अव्वल : मीणा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राजस्व एवं उपनिवेशन मंत्री हेमन्त मीणा ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल मार्गदर्शन में फार्मर रजिस्ट्री में पीएम किसान के 81 प्रतिशत पात्र लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन कर राजस्थान ने देश में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि उनके सफल प्रयासों का ही परिणाम है कि फार्मर रजिस्ट्री में प्रदेश के 73 लाख से अधिक किसानों का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। उन्होंने अधिकारियों को योजनाबद्ध रूप से कार्य कर फार्मर रजिस्ट्री के शत प्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त करने के निर्देश दिए।

मीणा बुधवार को शासन सचिवालय में वीसी के माध्यम से राजस्व तथा उपनिवेशन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को सीमाज्ञान,आपसी सहमति से बंटवारा, भू-रूपांतरण के लंबित प्रकरणों की प्रभावी मॉनिटरिंग कर त्वरित निस्तारण करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि किसानों के हितों को प्राथमिकता देते हुए सीमाज्ञान के लिए संचालित ई-धरती पोर्टल में आवश्यक संशोधन कर इसे और अधिक बेहतर बनाने की दिशा में कार्य करें। राजस्व मंत्री ने कहा कि राजस्व से संबंधित लंबित प्रकरणों का व्यवस्थित और समयबद्ध निस्तारण कर अधिकारी जीरो पेंडेंसी पर कार्य करना सुनिश्चित करें। बैठक में मीणा ने राजस्व मंडल एवं अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों, संभागीय आयुक्त न्यायालयों, जिला कलक्टर न्यायालयों के लंबित वादों की स्थिति की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि 10 से अधिक वर्षों से लंबित राजस्व वादों का प्रत्येक न्यायालय चिन्हित कर प्राथमिकता से गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करें।

राजस्व मंत्री ने कहा कि राइजिंग राजस्थान में किए गए एमओयू प्रदेश के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने समस्त जिला कलेक्टर्स को राजनिवेश पोर्टल के माध्यम से राइजिंग राजस्थान के भू आवंटन, नामांतरण दर्ज करने, संपरिवर्तन आदि प्रकरणों की जांच कर गुणवत्तापूर्ण व समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने वर्ष 2025-26 की बजट घोषणाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने उपनिवेशन विभाग द्वारा किए गए कार्यों की भी समीक्षा की।

प्रमुख शासन सचिव, राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग दिनेश कुमार ने कहा कि प्रदेश में फार्मर रजिस्ट्री में रजिस्ट्रेशन के लिए जिला कलेक्टर पटवार मंडल स्तरों पर डोर-टू-डोर रजिस्ट्रेशन चालू रखें, जिससे फार्मर रजिस्ट्री के शत प्रतिशत लक्ष्य को सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने बताया कि राज्य में डिजिटल क्रॉप सर्वे की दिशा में प्रभावी कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को भू रूपांतरण के प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश प्रदान किए।

बैठक में राजस्व मंडल अध्यक्ष हेमन्त कुमार गेरा ने मंडल द्वारा किये गए नवाचारों से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि राजस्व मंडल में प्रतिदिन 15 सबसे पुराने मामलों की सुनवाई अनिवार्य की गई है। इसके सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। मंडल अध्यक्ष ने बताया कि न्यायिक कार्य के लिए दो पारियों की शुरुआत की गई है, इससे राजस्व न्यायालयों की कार्यकुशलता तथा राजस्व प्रकरणों के निस्तारण प्रतिशत में सकारात्मक वृद्धि हुई है। विचाराधीन वाद जिसमें सरकार पक्षकार है, इनका प्राथमिकता से निस्तारण किया जा रहा है। बैठक में समस्त संभागीय आयुक्त, जिला कलक्टर्स एवं आयुक्त, उपनिवेशन वीसी के माध्यम से तथा निबंधक राजस्व मंडल, भू प्रबन्ध आयुक्त सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

मेवाड़ के पूर्व राजघराने के 'मुखिया' बने लक्ष्यराज सिंह

जयपुर। मेवाड़ के पूर्व राजपरिवार के सदस्य डॉ. लक्ष्यराज सिंह को बुधवार को उनके कुलगुरु डॉ. वागीश कुमार गोस्वामी ने 'गद्दी' पर बिठाया। उदयपुर के सिटी पैलेस में मंत्रोच्चार और शंखनाद के बीच यह भव्य अनुष्ठान संपन्न हुआ। इसके बाद सिंह ने अपने कुलगुरु समेत सभी संतों-महात्माओं का आशीर्वाद लिया। कार्यक्रम सिटी पैलेस के नौ चौकी महल के राय आंगन में हुआ, जहां लक्ष्यराज सहित सभी लोग सफेद धवल वस्त्र पहनकर आए थे। गद्दी (सिंहासन) की पूजा कर उस पर विराजमान होने के बाद लक्ष्यराज ने एकलिंग नाथ जी को पुष्प अर्पित कर धोक लगाई। उन्होंने धूणी दर्शन व अश्व पूजन सहित अन्य परंपराएं भी निभाईं और एकलिंगजी मंदिर में पूजा-अर्चना भी की। इस अवसर पर प्रांगण शाही शुभचिंतकों, गणमान्य व्यक्तियों व अन्य हस्तियों से भरा हुआ था। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए ओडिशा के उपमुख्यमंत्री और लक्ष्यराज के ससुर कनक वर्धन सिंह, जाने-माने कवि शैलेश लोढ़ा समेत कई लोग उदयपुर के सिटी पैलेस पहुंचे थे। लक्ष्यराज के पिता अरविंद सिंह मेवाड़ का 16 मार्च को निधन हो गया था।

उल्लेखनीय है कि कुछ महीने पहले ही नवंबर 2024 में चित्तौड़गढ़ किले में 'समानांतर राज्याभिषेक' हुआ था। लक्ष्यराज के चचेरे भाई और भाजपा विधायक विश्वराज सिंह को मेवाड़ का 77वां 'महाराणा' घोषित किया गया, जिससे इस पूर्व राजपरिवार की विरासत के 'असली' उत्तराधिकारी को लेकर कड़वाहट पैदा हो गई।

सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग निदेशक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की योजनाओं की समीक्षा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव बचनेश अग्रवाल ने कहा कि बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन में किसी भी तरह की लापरवाही या देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बजट घोषणाओं को धरातल पर उतारने की है। उन्होंने कहा कि अधिकारीगण 'माइक्रो प्लानिंग' कर घोषणाओं को मूर्त रूप देने में जुट जाएं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत के निर्देश पर अग्रवाल ने बुधवार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मुख्यालय 'अम्बेडकर भवन' स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल से जिला स्तरीय अधिकारियों से वीसी (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग) के जरिए बैठक ली और आवश्यक दिशानिर्देश दिए। इस दौरान निदेशालय सहित संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे। इस दौरान उन्होंने योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और संचालन के लिए अधिकारियों की प्रशंसा भी की तो कम प्रदर्शन करने वाले जिलों को मोटिवेट भी किया। उन्होंने कहा घोषणाओं की उच्च स्तर पर निरंतर समीक्षा की जा रही है, ऐसे में अधिकारीगण किसी भी स्तर पर कोरकसर नहीं छोडें।

अग्रवाल ने कहा किया बजट 2025-26 घोषणाओं की क्रियान्विति से पूर्व पिछले वर्ष की जो भी बजट घोषणाएं अपूर्ण हैं, उन्हें सबसे पहले पूरी करने पर जोर दें। उन्होंने बजट 2025-26 की घोषणाओं के अनुसार और आवश्यकता के अनुरूप भूमि चिन्हीकरण एवं आवंटन से जुड़ी गतिविधियों को तय समयावधि में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजनाओं के संचालन में समयबद्धता, गुणवत्ता और उपयोगिता पर विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। उन्होंने बजट घोषणाओं के कार्यों को रफ्तार देने की जरूरत पर भी जोर दिया।

बैठक के दौरान बाबा साहेब अंबेडकर आदर्श ग्राम योजना, स्वयंसिद्धा आश्रम, देवनारायण आवासीय योजना, कामकाजी महिला आवास योजना, बेघर वृद्धजन एवं असहाय निराश्रित व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु स्थापित किया जा रहे स्वयं सिद्ध आश्रमों, विमुक्त घुमंतू और अर्ध घुमंतु समुदायों के सशक्तिकरण एवं उत्थान की दृष्टि से दादू दयाल घुमंतू सशक्तिकरण योजना प्रारंभ करने, प्रदेश के एससी-एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, सफाई कर्मचारी, दिव्यांगजन आदि को आर्थिक संबल प्रदान करने की दृष्टि से अनुजा, ओबीसी एवं अल्पसंख्यक निगमों द्वारा दिए गए ऋणों के क्रम में वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लाने सहित अन्य विभिन्न विषयों पर विस्तार से समीक्षा की गई।

मुलाकात

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने मुलाकात की। शर्मा से उनकी यह शिष्टाचार भेंट थी। इस अवसर पर शर्मा ने विधानसभा अध्यक्ष को दुपट्टा ओढ़ाकर उनका अभिनंदन किया। इस दौरान दोनों के बीच विधायी प्रक्रियाओं, सुशासन और राज्यों के मध्य आपसी सहयोग सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई।

अनेक इलाकों में बादल छाए रहने का अनुमान

जयपुर। राजस्थान में एक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण अगले 48 घंटे में कई जगह बादल छाए रहने का अनुमान है। जयपुर में स्थित मौसम केंद्र ने यह जानकारी दी। केंद्र के अनुसार पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से पूर्वी व दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में अगले 48 घंटों में बादल छाए रहने का अनुमान है और तीन अप्रैल को जयपुर, भरतपुर व कोटा संभाग में मेघ गर्जन के साथ कहीं-कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। इस दौरान कहीं-कहीं अचानक 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। केंद्र के अनुसार आगामी 3-4 दिन में राज्य में न्यूनतम व अधिकतम तापमान में 3-5 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी हो सकती है और पांच व छह अप्रैल को बाड़मेर, जैसलमेर व आसपास के क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज होने व कहीं-कहीं हीटवेव (उष्ण लहर) चलने का अनुमान है।

इस बीच, बुधवार सुबह से पहले के चौबीस घंटे में राज्य में मौसम शुष्क रहा। इस दौरान सर्वाधिक अधिकतम तापमान बाड़मेर में 40.2 डिग्री सेल्सियस और सबसे कम न्यूनतम तापमान सीकर में 12.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

युवा कांग्रेस ने रोजगार मेला लगाया, कई युवाओं को मिले नियुक्ति पत्र

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। युवा कांग्रेस ने बुधवार को यहां राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में युवा रोजगार मेले का आयोजन किया। रोजगार मेले में प्रदेश के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में युवा पहुंचे। रोजगार मेले में सौ से अधिक बड़ी कंपनियों के अधिकारी मौजूद रहे और युवाओं का साक्षात्कार लिया। साक्षात्कार के बाद युवाओं को हाथों-हाथ 'नियुक्ति पत्र' भी दिए गए। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया ने एक बयान में कहा कि आज 2500 से अधिक युवाओं को 'नियुक्ति पत्र' दिए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि इस पहल की शुरुआत राजस्थान में प्रयोग के रूप में की गई है। अब इस तरह के आयोजन जिला और ब्लॉक स्तर पर भी किए जाएंगे। मेले में विभिन्न कंपनियों ने 'कियोस्क' लगाए गए, जहां युवाओं के साक्षात्कार लिए गए और उसके बाद उन्हें 'नियुक्ति पत्र' दिए गए। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि केंद्र और राज्य की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के बड़े-बड़े वादे किए, लेकिन रोजगार नहीं दिया।

युवा कांग्रेस की इस पहल का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि यह अच्छी बात है कि युवा कांग्रेस ने राहुल गांधी के संदेश को अमल में लाया है और लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि इस तरह के रोजगार मेले हर गली-मोहल्ले में लगने चाहिए, बड़ी-बड़ी कंपनियां आई हैं और लोगों को तुरंत नौकरी मिल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की भाजपा सरकार ने 'राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट' का खूब प्रचार किया, विदेश का दौरा किया और 33 लाख करोड़ के करार (एमओयू) करने का दावा किया। गहलोत ने कहा, अगर उनसे 10-12 हजार करोड़ भी आते हैं तो हम इसका स्वागत करेंगे कि कुछ निवेश आया है। हम इसका स्वागत करेंगे लेकिन अब मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि निवेशक फोन नहीं उठा रहे, ईमेल का जवाब नहीं दे रहे।

मौसमी बीमारियों से बचाव की हो पुख्ता तैयारियां, अलर्ट मोड में रहें अधिकारी : गजेन्द्र सिंह खींवसर

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने कहा कि मौसम विभाग के अनुसार इस वर्ष भी राजस्थान सहित देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी एवं हीटवेव की चेतावनी दी गई है। इसे देखते हुए सभी जिलों में अधिकारी अलर्ट मोड में रहते हुए जल्द से जल्द आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करें। किसी भी चिकित्सा संस्थान में जांच, दवा एवं उपचार से संबंधित व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं रहे। किसी भी स्तर पर लापरवाही सामने आई तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

चिकित्सा मंत्री बुधवार को स्वास्थ्य भवन में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आगामी गर्मियों में मौसमी बीमारियों से बचाव की तैयारियों सहित अन्य विषयों पर समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य स्तर से मौसमी बीमारियों से बचाव की तैयारियों की सतत मॉनिटरिंग की जाए। साथ ही, राज्य स्तर से अधिकारी नियमित रूप से फील्ड में जाकर निरीक्षण करें। साथ ही, संभाग एवं जिला स्तर के अधिकारी भी अपनेअपने क्षेत्र में आवश्यक रूप से निरीक्षण करें ताकि चिकित्सा व्यवस्थाएं चाकचौबंद रहें।

खींवसर ने सभी जिलों में चिकित्सकों एवं नर्सिंग स्टाफ की उपलब्धता की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि जहां भी डॉक्टर्स या नर्सिंग स्टाफ पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं है, वहां वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। स्थानीय स्तर पर नियमानुसार संविदा आधार पर चिकित्सक या अन्य चिकित्साकर्मियों की सेवाएं ली जाएं। उन्होंने गुरूवार दोपहर तक सभी जिलों से चिकित्सा संस्थानों में मानव संसाधन की स्थिति की विस्तृत जानकारी भिजवाने के निर्देश दिए।

चिकित्सा मंत्री ने कहा कि किसी भी चिकित्सा संस्थान में पंखे, कूलर, एसी आदि की कमी की शिकायत नहीं आए। समय रहते जरूरी संसाधनों की खरीद एवं मेंटीनेंस सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए तात्कालिक आवश्यकतानुसार आरएमआरएस में उपलब्ध राशि का नियमानुसार उपयोग किया जाए। साथ ही, दानदाताओं, स्वयंसेवी संस्थाओं एवं भामाशाहों से भी सहयोग लिया जा सकता है। खींवसर ने कहा कि जिलों में कंट्रोल रूम स्थापित कर उनका सुचारू संचालन किया जाए। सभी अस्पतालों में आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्थाएं पुख्ता हों। एम्बुलेंस की क्रियाशीलता एवं उसमें सभी जीवन रक्षक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित हो। आमजन को मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए जागरूक करने के निर्देश भी दिए। खींवसर ने सभी जिलों में ट्रोमा सेंटर्स एवं एफआरयू के सुचारू संचालन की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि लोगों का जीवन बचाने में ट्रोमा सेंटर्स की भूमिका महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार इन सेंटर्स में आवश्यक मानव संसाधन एवं उपकरण उपलब्ध करवाकर इनकी क्रियाशीलता सुनिश्चित कर रही है। जहां भी आवश्यक मानव संसाधन एवं उपकरणों की कमी के कारण ट्रोमा सेंटर व एफआरयू का संचालन प्रभावित हो रहा है, वहां जल्द से जल्द रिक्त पदों को भरा जाएगा।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि विभाग प्रो-एक्टिव एप्रोच के साथ समय रहते आगामी गर्मियों में मौसमी बीमारियों से बचाव एवं उपचार की जरूरी तैयारियां सुनिश्चित कर रहा है। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सक या अन्य स्टाफ की कमी है, वहां जल्द से जल्द वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित कर पदों को भरा जाए, ताकि स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित नहीं हों। दवाओं की समयबद्ध रूप से समुचित आपूर्ति सुनिश्चित की जाए और अधिकारी नियमित रूप से व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग करें।

बैठक में चिकित्सा शिक्षा सचिव अम्बरीष कुमार, आरएमएससीएल की प्रबंध निदेशक नेहा गिरि, राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एजेंसी की मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रियंका गोस्वामी, अतिरिक्त मिशन निदेशक एनएचएम डॉ. टी. शुभमंगला, निदेशक जनस्वास्थ्य डॉ. रवि प्रकाश शर्मा, निदेशक अराजपत्रित राकेश शर्मा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे। मेडिकल कॉलेजों के प्रधानाचार्य, अधीक्षक, संयुक्त निदेशक जोन, सीएमएचओ, पीएमओ सहित अन्य अधिकारी भी वीसी से जुड़े।

प्रदेश सरकार प्रत्येक नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध : पटेल

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक मंत्री जोगाराम पटेल ने बुधवार को प्राथमिक जोधपुर जिले के स्वास्थ्य केन्द्र पूनियों की प्याऊ का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान जनरल ओपीडी, इंजेक्शन एवं ड्रेसिंग कक्ष, लेबोरेटरी कक्ष, लेबर वार्ड,टीकाकरण कक्ष,पंजीकरण रजिस्टर एवं दवाओं के स्टॉक का अवलोकन कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के संवेदनशील नेतृत्व में प्रदेश सरकार प्रत्येक नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही हैं। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत आमजन की निःशुल्क जाँच एवं दवा के लिए 3500 करोड़ रुपये के 'मा कोष' का गठन किया जाएगा।

पटेल ने कहा क्षेत्रवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र में अनेक सौगातें मिली हैं जिसमें केरू में ट्रॉमा सेंटर क्षेत्रवासियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं हैं। संसदीय कार्य मंत्री ने अभियान चलाकर अस्पताल परिसर एवं सभी वार्ड्स में सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी कार्मिकों को निर्देश दिए कि अस्पताल में समय पर उपस्थित रहकर मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराएं। पटेल ने रजिस्ट्रेशन काउंटर,आवश्यक सामग्री एवं शुद्ध पेयजल सहित अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने ने कहा कि मरीजों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो,चिकित्सक इसका विशेष ध्यान रखें। उन्होंने अस्पताल के वार्डों के अवलोकन के दौरान मरीजों एवं उनके परिजनों से बातचीत कर राज्य सरकार द्वारा मिल रही निःशुल्क दवा, निःशुल्क जांच सहित अन्य सुविधाओं का फीडबैक लिया।

प्रदेश में 5 हजार करोड़ की लागत से नेशनल हाइवे बनेगें : दीया कुमारी

जयुपर। उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने बताया कि प्रदेश में 21 नेशनल हाईवे परियोजनाओं के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा लगभग 5 हजार करोड़ की लागत की नई परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके तहत नागौर नेत्रा सड़क के 4 लेन का कार्य, रायपुर जस्साखेड़ा, गंगापुर सिटी बाईपास, करौली बाईपास सहित विभिन्न सड़कों का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा करवाया जायेगा । इसके साथ ही दुर्घटना सम्भावित 13 ब्लैक स्पाटस के सुधार का कार्य भी करवाया जायेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नीतिन गड़करी का इस स्वीकृति के लिए धन्यवाद दिया है। उपमुख्यमंत्री ने कहा है की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश की डबल इंजन सरकार विकास के नये प्रतिमान स्थापित कर रही है।

जयपुर में सीरियल ब्लास्ट की साजिश रचने वाला आरोपी रतलाम में गिरफ्तार

जयपुर। राजस्थान के जयपुर को सीरियल ब्लास्ट से दहलाने की साजिश रचने वाले आखिरी फरार आरोपी फिरोज उर्फ़ सब्जी की गिरफ्तारी एक बड़ी सफलता मानी जाएगी। रतलाम पुलिस और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (छ्ख–) की सतर्कता ने आतंकवादी संगठनों की मंशा पर करारा प्रहार किया है। इस गिरफ्तारी से न केवल कानून-व्यवस्था को मजबूती मिली है, बल्कि यह भी स्पष्ट हुआ है कि आतंक के खिलाफ सरकार और सुरक्षा एजेंसियां पूरी मुस्तैदी से कार्य कर रही हैं। फिरोज उर्फ़ सब्जी, जिसे अल-सुफा संगठन का खजांची माना जाता है, लंबे समय से फरार था और उस पर छ्ख– द्वारा 5 लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया था। यह गिरफ्तारी पुलिस और खुफिया एजेंसियों के मजबूत नेटवर्क और अत्याधुनिक जांच तकनीकों का परिणाम है। जिस तरह से रतलाम पुलिस ने कई स्तरों पर ऑपरेशन को अंजाम दिया और संभावित ठिकानों की निगरानी करते हुए आरोपी को धर दबोचा, वह अन्य राज्यों के लिए भी एक मिसाल है। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में सक्रिय आतंकी संगठन, जिन्हें बाहरी फंडिंग और वैचारिक समर्थन प्राप्त होता है, अब कानून के शिकंजे में आ रहे हैं। जयपुर ब्लास्ट की योजना बनाने वाले इस मॉड्यूल का खुलासा बताता है कि ये आतंकी संगठन अब भी देश को अस्थिर करने की मंशा रखते हैं, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता के चलते वे अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पा रहे।

फिरोज की गिरफ्तारी निस्संदेह एक बड़ी सफलता है, लेकिन यह सवाल भी उठता है कि क्या यह गिरफ्तारी ही पर्याप्त है? हमें यह समझना होगा कि आतंकवाद केवल हथियारों और विस्फोटकों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक वैचारिक युद्ध भी है। जब तक ऐसे संगठनों की विचारधारा और उनके समर्थकों पर गहरी चोट नहीं की जाएगी, तब तक यह खतरा बना रहेगा।

संसद पर भी था वक्फ का दावा

वक्फ संपत्तियों का सही प्रबंधन होता तो देश की तकदीर बदल जाती : रीजीजू

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। सरकार ने बुधवार को कहा कि अगर वह वक्फ संशोधन विधेयक नहीं लाती तो संसद भवन समेत कई इमारतें दिल्ली वक्फ बोर्ड के पास चली जातीं और कांग्रेस के शासनकाल में वक्फ संपत्तियों का सही से प्रबंधन होता तो केवल मुसलमानों की ही नहीं, बल्कि देश की तकदीर भी बदल जाती। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को चर्चा और पारित कराने के लिए रखते हुए यह भी कहा कि इसके माध्यम से सरकार और वक्फ बोर्ड मस्जिद समेत किसी धार्मिक संस्था के किसी धार्मिक कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करेंगे।

■ दुनिया में सबसे अधिक वक्फ संपत्ति भारत में है और इतनी अकूत जायदाद होने के बाद भी इतने सालों तक गरीब मुसलमानों के उत्थान के लिए, उनकी शिक्षा के लिए काम क्यों नहीं हुआ?

उन्होंने वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ विपक्षी दलों के दावों को खारिज करते हुए कहा कि 1995 में जब कई संशोधनों के साथ व्यापक कानून बनाया गया था, तब किसी ने नहीं कहा था कि यह असंवैधानिक और गैरकानूनी है। रीजीजू ने कहा, ''आज हम इसे सुधार कर ला रहे हैं तो यह असंवैधानिक लग रहा है। तर्कों पर बात कीजिए। जिन बातों का विधेयक से कोई लेनादेना नहीं, उन पर बात की जा रही है और लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है।'' उन्होंने कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार मस्जिद, दरगाह और मुसलमानों की संपत्तियों को छीन लेगी जो पूरी तरह गुमराह करने वाली बात है।

रीजीजू ने साफ किया कि यह विधेयक पूर्वगामी प्रभाव से लागू नहीं होगा। उन्होंने इस विधेयक की जरूरत के कारण गिनाते हुए कहा कि 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले 2013 में तत्कालीन संप्रग सरकार ने कुछ ऐसे कदम उठाए जिनसे कई संपत्तियां दिल्ली वक्फ बोर्ड के पास चली जातीं। रीजीजू ने कहा कि 2013 में पहली बार वक्फ कानून में यह बदलाव किया गया कि इस देश में किसी भी धर्म का व्यक्ति वक्फ बना सकता है। उन्होंने कहा कि इनके अलावा ऐसे प्रावधान किए गए कि शिया वक्फ में शिया ही रहेंगे, सुन्नी वक्फ में सुन्नी ही रहेंगे तथा बाहर से कोई और नहीं आ सकता। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने कहा, एक धारा में तो यह तक लिखा गया कि वक्फ बोर्ड का कानून किसी भी मौजूदा कानून के ऊपर रहेगा। इस देश में ऐसा कानून कैसे मंजूर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली स्थित इस संसद भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स समेत कई संपत्तियों पर दिल्ली वक्फ बोर्ड का दावा था। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने से ऐन पहले 5 मार्च 2014 को उस समय की संप्रग सरकार ने आवासन और शहरी विकास मंत्रालय के अधीन 123 मुख्य संपत्तियों को दिल्ली वक्फ बोर्ड को हस्तांतरित कर दिया।

रीजीजू ने कांग्रेस पर हमलावर होते हुए कहा, कुछ दिन इंतजार करते। आपको लगा कि वोट मिलेंगे, लेकिन आप चुनाव में हार गए। ऐसे काम से वोट नहीं मिलता। देश की जनता समझदार है। रीजीजू ने कहा, आज हम ये संशोधन लेकर नहीं आते तो इस संसद भवन पर भी दावा किया जा रहा था। अगर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राजग सरकार नहीं आती तो न जाने कितने भवन वक्फ को चले जाते।

उन्होंने कहा कि दुनिया में सबसे अधिक वक्फ संपत्ति भारत में है और इतनी अकूत जायदाद होने के बाद भी इतने सालों तक गरीब मुसलमानों के उत्थान के लिए, उनकी शिक्षा के लिए काम क्यों नहीं हुआ? रीजीजू ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में गरीब मुसलमानों के हित में काम हो रहा है तो क्या आपत्ति है। सही तरीके से देश में वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन होता तो मुस्लिम समुदाय और देश दोनों की ही तकदीर बदल जाती।

कांग्रेस के समय संसदीय समितियां केवल ठप्पा लगाती थीं, आज चर्चा करके परिवर्तन करती हैं : अमित शाह

नई दिल्ली/भाषा। वक्फ (संशोधन) विधेयक पर संसद की संयुक्त समिति के विचार-विमर्श करने की पृष्ठभूमि में गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि कांग्रेस की सरकार के समय संसद की समितियां केवल ठप्पा लगाती थीं, लेकिन आज वे लोकतांत्रिक तरीके से चर्चा करके परिवर्तन करती हैं। लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को चर्चा और पारित कराने के लिए प्रस्तुत किया गया तो आरएसपी के एन के प्रेमचंद्रन ने दावा किया कि विधेयक में संसद की संयुक्त समिति के प्रावधान शामिल किए गए हैं जो नियम एवं प्रक्रियाओं के अनुरूप नहीं है। उन्होंने दावा किया कि समिति ने अधिकार से परे जाकर प्रावधान जोड़े हैं और यह बहुत गंभीर तकनीकी मामला है।

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत सरकार के मंत्रिमंडल ने सबसे पहले इस संबंध में एक विधेयक को मंजूरी दी थी जिसे पूर्व में सदन के सामने रखा गया था। उन्होंने कहा, ''विधेयक संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया, जिसके लिए विपक्ष ने भी आग्रह किया था। समिति ने इस पर सुविचारित रूप से अपना मत प्रकट किया। उसके सुझाव के अनुसार विधेयक को फिर से मंत्रिमंडल के सामने भेजा गया।'' शाह ने कहा कि संसदीय समिति के सुझावों को मंत्रिमंडल ने स्वीकार किया और उसे ही संशोधनों के रूप में अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रीजीजू बुधवार को सदन में लेकर आए हैं।

गृह मंत्री ने कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए कहा, आपका ही आग्रह था कि जेपीसी बने। समिति को यदि कोई बदलाव ही नहीं करना था तो क्या फायदा। यह कांग्रेस की सरकार के समय जैसी समिति नहीं थी, यह लोकतांत्रिक समिति है जिसने मंथन किया। उन्होंने कहा कि समिति ने चर्चा करके संशोधन सुझाए।

एक विशेष समुदाय की जमीन पर सरकार की नजर, वक्फ पर प्रस्तावित कानून से मुकदमेबाजी बढ़ेगी : कांग्रेस

नई दिल्ली/भाषा। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने लोकसभा में बुधवार को आरोप लगाया कि एक विशेष समुदाय की जमीन पर सरकार की नजर है। उन्होंने दावा किया कि मौजूदा वक्फ कानून में संशोधन होने पर देश में मुकदमेबाजी बढ़ेगी। उन्होंने सदन में वक्फ (संशोधन) विधेयक पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि वह यह नहीं कर रहे हैं कि संशोधन की जरूरत नहीं है, बल्कि संशोधन होना चाहिए और हम इसके विरोध में नहीं हैं।'' गोगोई ने कहा, ...यह कानून को और मजबूत बनाने के लिए होना चाहिए लेकिन इस विधेयक से देश में और समस्या बढ़ेगी, मसले बढ़ेंगे और मुकदमेबाजी भी बढ़ेगी।

लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रीजीजू पर हमला करते हुए कहा कि उन्होंने अपने भाषण में राजनीतिक आरोप लगाये और सदन को गुमराह किया। इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच नोकझोंक देखी गई। गोगोई ने कहा, आपने संप्रग सरकार के कार्यकाल के बारे में जो कुछ भी कहा, उसे साबित करें। आपने बार-बार आरोप लगाया, भ्रम फैलाया। कृपया आप भी सुनने का धैर्य रखें...।

कांग्रेस सांसद ने कहा कि यह विधेयक संविधान के मूल ढांचे पर आक्रमण है। गोगोई ने आरोप लगाया कि इस विधेयक को लाने का मूल उद्देश्य संविधान को कमजोर करना, भ्रम फैलाना, अल्पसंख्यक समुदायों को अपमानित करना तथा भारतीय समुदाय को विभाजित करना है ताकि हमारे बीच विवाद चलता रहे और मसला बढता रहे। उन्होंने सवाल किया, लोकसभा में आपके कितने अल्पसंख्यक सांसद हैं, इसी से पता चल जाएगा कि आपके दिल में (मुसलमानों के प्रति) कितनी संवेदना है?

संसद को वक्फ के संबंध में कानून पारित करने का कोई अधिकार नहीं : तृणमूल कांग्रेस

नई दिल्ली/भाषा। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को राज्यों के अधिकारों पर अतिक्रमण करने वाला बताते हुए बुधवार को दावा किया कि संसद को इस संबंध में कानून पारित करने का कोई अधिकार नहीं है। विधेयक पर सदन में हुई चर्चा में भाग लेते हुए बनर्जी ने कहा कि मुसलमानों को अपनी संपत्ति का अधिकार है और वक्फ संपत्ति मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान है। उन्होंने विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि ऐसे कानून पारित करने का अधिकार केवल राज्यों का है और यह विधेयक पूरी तरह असंवैधानिक है। तृणमूल कांग्रेस सांसद ने कहा कि संवैधानिक प्रावधान संसद को ऐसे विधेयक लाने का अधिकार नहीं देते। उन्होंने कहा कि इस तरह से संसद के माध्यम से राज्य विधायिका के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता।

बनर्जी ने यह भी कहा कि प्रस्तावित विधेयक कानून के उन भलीभांति स्थापित सिद्धांतों को खारिज करता है जिन्हें उच्चतम न्यायालय और अन्य न्यायालयों ने विभिन्न मामलों में निर्धारित किया है। उन्होंने कहा कि सरकार को यह पूछने का अधिकार किसने दिया कि कोई अपनी धार्मिक जिम्मेदारी अदा कर रहा है या नहीं।

बनर्जी ने वक्फ संशोधन विधेयक में पांच साल तक इस्लाम के अनुसरण के बाद ही वक्फ बनाने संबंधी प्रावधानों का उल्लेख करते हुए कहा, मैं कभी भी हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और बौद्ध में से किसी भी संस्था को अपनी संपत्ति दान में दे सकता हूं। उन्होंने कहा कि अगर लंबित मामलों को इस विधेयक को लाने का आधार बताया गया है तो उच्चतम न्यायालय और अन्य अदालतों में बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं।

वक्फ संपत्तियों के लिए सही नहीं वक्फ संशोधन विधेयक : एआईएमपीएलबी

लखनऊ/वाराणसी/भाषा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) ने वक्फ संशोधन विधेयक पर कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि यह वक्फ संपत्तियों के लिए लाभकारी होने के बजाय नुकसानदेह होगा। एआईएमपीएलबी के वरिष्ठ कार्यकारी सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने 'पीटीआई-भाषा' से कहा, एआईएमपीएलबी और अन्य मुस्लिम संगठनों ने विधेयक पर अपनी चिंताओं से संयुक्त संसदीय समिति को अवगत कराया था, लेकिन इस पर विचार नहीं किया गया। इसके बाद, दिल्ली और पटना समेत कई शहरों में विरोध प्रदर्शन किए गए जहां प्रदर्शनकारियों ने असहमति दर्ज कराने के लिए सांकेतिक रूप से काली पट्टी बांधी। उन्होंने कहा, ''हमने सभी सांसदों से मुस्लिम समुदाय की भावनाओं पर विचार करने और प्रस्तावित संशोधनों को खारिज करने का आग्रह किया है।'' इस बीच, वाराणसी में विभिन्न अदालती मामलों में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि विधेयक ने वक्फ बोर्डों के पहले के कई अधिकारों को कम कर दिया है, जो एक सकारात्मक कदम है। जैन ने कहा, यह विधेयक वक्फ की परिभाषा में महत्वपूर्ण बदलाव करता है और इसकी अनियंत्रित शक्तियों को सीमित करता है। यह एक स्वागत योग्य कदम है, लेकिन कुछ पहलुओं पर अभी भी ध्यान देने और बहस की आवश्यकता है।

वक्फ धार्मिक संस्था नहीं वैधानिक संस्था है, पिछड़े मुसलमानों को इसमें जगह दी जाएगी : रविशंकर प्रसाद

नई दिल्ली/भाषा। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद रविशंकर प्रसाद ने वक्फ को धार्मिक संस्था के बजाय ''वैधानिक संस्था'' करार देते हुए बुधवार को लोकसभा में कहा कि मौजूदा कानून में संशोधन के जरिये यदि पिछड़े मुसलमानों को भी इसमें जगह देने की बात कही जा रही है तो इसमें विपक्षी दलों को क्या परेशानी है। उन्होंने वक्फ (संशोधन) विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि देश में वक्फ की आठ लाख संपत्ति है, लेकिन इनमें से कितने पर स्कूल, अस्पताल बने, कौशल विकास केंद्र खोले गए, अनाथालय बने और विधवाओं या बेटियों को सिलाई-कढ़ाई सिखाने की व्यवस्था की गई?

भाजपा सांसद ने विपक्षी दलों पर हमला करते हुए सवाल किया, ''वक्फ की फंडिंग बढ़ने पर उस जमात का कल्याण होगा तो उन्हें क्या परेशानी है।'' उन्होंने कहा, आप इस विधेयक का विरोध क्यों कर रहे हैं? आपको इस विधेयक से क्या परेशानी है? क्या आप नहीं चाहते कि वक्फ की संपत्ति गरीबों, पसमांदा मुसलमानों और बेटियों के काम आए...।'' पूर्व कानून मंत्री ने कहा, मैं जिस प्रदेश, बिहार से आता हूं वहां पिछड़े मुसलमान भी हैं। उत्तर प्रदेश में भी बड़ी संख्या में ये लोग हैं। लेकिन पसमांदा (पिछड़े) मुसलमानों को वक्फ में अधिकार नहीं मिलता। यदि पिछड़े मुसलमानों को भी वक्फ में जगह देने की बात की जा रही, तो उन्हें क्या परेशानी है?'' उन्होंने विपक्षी दलों के कुछ नेताओं पर तंज कसते हुए कहा, आजकल लाल किताब लेकर बहुत से लोग घूमते हैं, जब भी कोई बात होती है इसे दिखाया जाता है।''

उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 15 का उल्लेख करते हुए कहा कि इसमें लिखा है कि सरकार महिलाओं के विकास के लिए कानून बना सकती है, अब वक्फ में उनकी भूमिका के लिए कानून लाया जा रहा तो यह गैर कानूनी कैसे हो गया। प्रसाद ने कहा कि इसी अनुच्छेद में यह भी लिखा है कि सरकार सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए काम कर सकती है और वक्फ अधिनियम में संशोधन की अनुमति अनुच्छेद 15 से मिलती है।

सेवानिवृत्ति वाले दिन लोको पायलट की मालगाड़ियों की टक्कर में हुई मौत

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

कोलकाता/भाषा। झारखंड के साहेबगंज जिले में दो मालगाड़ियों के बीच टक्कर में मारे गए एनटीपीसी के लोको पायलट गंगेश्वर मल एक अप्रैल को सेवानिवृत्त होने वाले थे और यह सेवा में रहने के दौरान उनकी अंतिम यात्रा थी। लोको पायलट के परिवार की योजना थी कि सेनानिवृत्ति वाले दिन पूरा परिवार साथ में रात्रि भोज करेगा लेकिन अब उनके पास केवल यादें और आंसू हैं।

गंगेश्वर मल का परिवार पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में जियागंज स्थित घर में रहता है, उनके परिवार के सदस्यों ने बताया कि उन्होंने काम से लौटने के बाद रात का खाना साथ में खाने का वादा किया था। उनकी बेटी ने बताया कि एक अप्रैल उनके पिता का आखिरी कार्य दिवस था, जिसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी, बेटे और बेटी के साथ अच्छा समय बिताने की योजना बनाई थी।

उन्होंने कहा, हमने सुना कि बाबा (पिता) वापसी में सिग्नल प्वाइंट पर इंतजार कर रहे थे, तभी विपरीत दिशा से आ रही एक अन्य मालगाड़ी के इंजन ने उनके इंजन को सामने से टक्कर मार दी। मंगलवार को बरहेट थाना क्षेत्र के भोगनाडीह के पास देर रात तीन बजे हुई इस दुर्घटना में एक अन्य लोको पायलट की भी मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गए।

एनटीपीसी द्वारा संचालित मालगाड़ियां फरक्का में थर्मल पावर प्लांट में कोयला ले जा रही थीं। साहेबगंज के अनुमंडल पुलिस अधिकारी किशोर तिर्की ने बताया, आमने-सामने की टक्कर में दोनों मालगाड़ियों के चालकों की मौत हो गई। पूर्वी रेलवे के प्रवक्ता कौशिक मित्रा ने स्पष्ट किया कि यह घटना एनटीपीसी के बुनियादी ढांचे से जुड़ी है।

मित्रा ने कहा, ''मालगाड़ियां और पटरियां एनटीपीसी की हैं। इसका भारतीय रेलवे से कोई लेना-देना नहीं है।''

नीलकंठ महादेव मंदिर बनाम जामा मस्जिद मामले की सुनवाई 21 तक स्थगित

बदायूं (उप्र)/भाषा। नीलकंठ महादेव मंदिर और शम्सी जामा मस्जिद से संबंधित विवाद की स्थानीय अदालत में जारी सुनवाई न्यायाधीश के स्थानांतरण के कारण बुधवार को स्थगित कर दी गई। एक वकील ने यह जानकारी दी। वकील ने बताया कि मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति अमित कुमार का तबादला भदोही कर दिया गया है और उनकी अदालत रिक्त है, इसलिए मामले की सुनवाई 21 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। न्यायाधीश अमित कुमार की त्वरित अदालत ने इससे पहले मुस्लिम पक्ष को अदालत में उपस्थित होने का अंतिम अवसर दिया था। मुस्लिम पक्ष के कानूनी प्रतिनिधि अदालत में पेश नहीं हो रहे थे। अदालत की ओर से लगातार समन भेजे जाने के बावजूद मस्जिद की प्रबंधन समिति के वकील उपस्थित नहीं हुए। इसके बाद न्यायाधीश ने उन्हें अपना मामला प्रस्तुत करने के लिए अंतिम अवसर के रूप में 11 फरवरी की तारीख तय की थी। हालांकि वकीलों की हड़ताल के कारण सुनवाई 10 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई और फिर इसे 20 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

भारतीय नौसेना ने 2500 किलो मादक पदार्थ बरामद किया

नई दिल्ली/भाषा। भारतीय नौसेना के अग्रणी युद्धपोत आईएनएस तरकश ने पश्चिमी हिंद महासागर में 2,500 किलोग्राम से अधिक मादक पदार्थ जब्त किया है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि 31 मार्च को नौसेना को कुछ जहाजों की संदिग्ध गतिविधियों के बारे में सूचना मिली थी, जिसके बाद मादक पदार्थों को जब्त करने का अभियान शुरू किया गया। नौसेना के प्रवक्ता ने बताया कि आसपास के सभी संदिग्ध जहाजों या नौकाओं से पूछताछ करने के बाद आईएनएस तरकश ने पी8आई समुद्री निगरानी विमान और मुंबई में समुद्री परिचालन केंद्र के साथ मिलकर एक संदिग्ध नौका को रोका और उसमें सवार हो गये। उन्होंने बताया कि इसके अलावा, जहाज ने संदिग्ध नौका की गतिविधियों पर नजर रखने और क्षेत्र में संभावित रूप से संचालित अन्य जहाजों की पहचान करने के लिए अपने हेलीकॉप्टर को भी भेजा। अधिकारी ने बताया कि मरीन कमांडो के साथ एक विशेषज्ञ टीम नौका पर सवार हो गयी और गहन तलाशी ली जिसके परिणामस्वरूप कई सीलबंद पैकेट बरामद हुए। उन्होंने बताया कि तलाशी और पूछताछ में पता चला कि जहाज पर विभिन्न कार्गो होल्ड और डिब्बों में 2,500 किलोग्राम से अधिक मादक पदार्थ (जिसमें 2,386 किलोग्राम हशीश और 121 किलोग्राम हेरोइन शामिल है) रखे हुए थे। प्रवक्ता ने बताया कि संदिग्ध नौका को बाद में आईएनएस तरकश के नियंत्रण में लाया गया।

मणिपुर में हजारों शरणार्थी 60 के दशक से रह रहे हैं : बीरेन

■ 1960 के दशक के अंत और 70 के दशक की शुरुआत में, दस्तावेजों से पता चलता है कि 1,500 से अधिक परिवार सीमा पार कर यहां आए थे और उन्हें पुनर्वास के लिए सहायता प्रदान की गई थी।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

इंफाल/भाषा। मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने बुधवार को कहा कि 1960 के दशक से हजारों शरणार्थी अधिकारियों की जानकारी में राज्य में आकर बसे हुए हैं और उन लोगों को पुनर्वास के लिए सहायता प्रदान की गई है। सिंह ने आश्चर्य जताया कि उन परिवारों का क्या हुआ और क्या उन लोगों के नाम मतदाता सूची में जोड़े गए हैं? सिंह ने मणिपुर के मुख्यमंत्री पद से फरवरी में इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था।

बीरेन सिंह ने यह टिप्पणी 'एक्स' पर एक पोस्ट में की। मणिपुर के भाजपा विधायकों ने राज्य में परिसीमन करने से पहले 2001 की जनगणना की !!समीक्षा'' और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के कार्यान्वयन की मांग की थी। इसके एक दिन बाद, पूर्व मुख्यमंत्री की यह टिप्पणी आई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते सिंह ने और केंद्र ने म्यांमा से आए अवैध प्रवासियों को राज्य में भड़की जातीय हिंसा के लिए बड़े पैमाने पर जिम्मेदार ठहराया था। इस हिंसा में मई 2023 से अब तक 250 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं।

सिंह ने पोस्ट में कहा, आधिकारिक रिकॉर्ड बताते हैं कि हमारे पूर्ण राज्य बनने से पहले ही, हजारों शरणार्थियों को उस समय के अधिकारियों की जानकारी में यहां बसाया गया था। 1960 के दशक के अंत और 70 के दशक की शुरुआत में, दस्तावेजों से पता चलता है कि 1,500 से अधिक परिवार सीमा पार कर यहां आए थे और उन्हें पुनर्वास के लिए सहायता प्रदान की गई थी। मणिपुर एक नवंबर, 1956 को केंद्र शासित प्रदेश बना और 21 जनवरी 1972 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया।

सिंह ने पूछा, ''उन परिवारों का क्या हुआ। तब से अब तक कितनी पीढ़ियां बड़ी हो गई हैं... क्या उन्हें अंततः पूर्ण अधिकार दे दिए गए? क्या उनके नाम मतदाता सूची में जोड़े गये?'' भाजपा नेता ने दावा किया कि इन सवालों का कभी भी सार्वजनिक रूप से पूरी तरह से समाधान नहीं किया गया और इस मुद्दे पर काफी हद तक चुप्पी बनी रही जबकि राज्य की जनसांख्यिकीय संरचना पिछले कुछ वर्षों में बदल गई है।

उन्होंने कहा कि मणिपुर के तत्कालीन सांसद पाओकाई हाओकिप ने गृह राज्य मंत्री के.सी. पंत को एक पत्र लिखकर बताया था कि 1967 तक मणिपुर में 1,500 से अधिक शरणार्थी परिवार बस गये थे। इसके साथ ही सिंह ने इस पत्र की एक प्रति सोशल मीडिया मंच पर साझा की। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, उनका (तत्कालीन सांसद का) पत्र कई पत्रों में से एक है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि यह मुद्दा कितना गहरा है।

इस बात पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कि क्या मणिपुर शुरू से ही शरणार्थियों के लिए ''डंपिंग ग्राउंड'' था, सिंह ने कहा कि यह पूछना महत्वपूर्ण है कि क्या इन व्यक्तियों को शरणार्थी की स्थिति में बनाए रखने के लिए कोई कानूनी तंत्र था।

सुविचार

शांति वह लक्ष्य है जिसकी ओर सभी धर्मों का मार्गदर्शन करना चाहिए।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

ज़ेलेंस्की के पदचिह्नों पर यूनुस?

बांग्लादेश के 'मुख्य सलाहकार' मोहम्मद यूनुस ने जब से यह जिम्मा संभाला है, उन्होंने 'अर्थशास्त्र' के ज्ञान को तिलांजलि देकर 'अनर्थशास्त्र' के नए-नए अध्याय लिखने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के संबंध में जो टिप्पणी की है, उससे यह स्पष्ट होता है कि वे चीन की कठपुतली बनने के लिए तैयार हैं। उनकी यह टिप्पणी कि 'बांग्लादेश महासागर (बंगाल की खाड़ी) का एकमात्र संरक्षक है, क्योंकि भारत के पूर्वोत्तर राज्य चारों ओर से जमीन से घिरे हैं और उनके पास समुद्र तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है ... इससे बड़ी संभावनाएं खुलेंगी और चीन को बांग्लादेश में अपना आर्थिक प्रभाव बढ़ाना चाहिए ...', अत्यंत निंदनीय है। ऐसा प्रतीत होता है कि मोहम्मद यूनुस यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के पदचिह्नों पर चलना चाहते हैं, जिन्होंने अविवेकपूर्ण ढंग से फैसले लेकर अपने ही देश को तबाह कर दिया। यूनुस दिखाना चाहते हैं कि बांग्लादेश में इतनी शक्ति व सामर्थ्य मौजूद है कि यह महासागर का बहुत बड़ा रखवाला बन गया है, इतना बड़ा कि जो इसके साथ जुड़ेगा, वह अंतरराष्ट्रीय व्यापार में बहुत उन्नति करेगा! अगर बांग्लादेश में सच में इतनी बड़ी संभावनाएं आकार ले चुकी हैं तो यूनुस सबसे पहले अपने देशवासियों का भला क्यों नहीं कर देते? क्यों वे जंगल, नदियों और तारों की बाड़ को पार करते हुए भारत में घुसपैठ करते हैं? क्यों वे हमारे विभिन्न शहरों में फर्जी नाम और पहचान के साथ रहने को मजबूर होते हैं? यूनुस चीन के लिए संभावनाएं बाद में तलाशें, पहले बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की लूटमार और हिंसा पर लगाम लगाने पर विचार करें। वे चीन को जिस तरह बड़ी संभावनाओं के सब्ज़-बाग़ दिखाकर न्योता दे रहे हैं, कहीं वह भविष्य में बांग्लादेश के लिए गले का फंदा न बन जाए।

चीन ने अपना प्रभाव पाकिस्तान में बढ़ाया, सीपेक बनाया, ऊंची ब्याज दरों पर कर्ज दिया, बलोचिस्तान की खनिज संपदा को लूटने की साजिश रची ... इससे वहां लोग आक्रोशित हैं। आज पाकिस्तान के राजस्व का एक बड़ा हिस्सा तो चीनी कर्ज का ब्याज चुकाने में चला जाता है। चीन ने श्रीलंका में हंबनटोटा बंदरगाह के साथ क्या किया? उसने मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्ज़ू की खूब पीठ थपथपाई थी, जिससे उत्साहित होकर वे और उनके मंत्री भारत को आंखें दिखाने लगे थे। उससे मालदीव की अर्थव्यवस्था को क्या हासिल हुआ? मोहम्मद यूनुस को इन सबसे सबक लेना चाहिए। वे चीन के साथ जिस तरह गलबहियां कर रहे हैं, भारतविरोधी बयान दे रहे हैं, उसके बाद यह न समझें कि भारत से उन्हें कोई नहीं देख रहा है। उनके एक-एक शब्द के सही-सही मायने निकाले जा रहे हैं। वे हमारे देश के क्षेत्रों का उल्लेख कर चीनी एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। अपने पड़ोसियों द्वारा की गई ऐसी टीका-टिप्पणी पर भारत ने सदैव धैर्य और सहनशीलता का परिचय दिया है, लेकिन बात जब हमारे देश की अखंडता और सुरक्षा की होगी तो इन पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। उस सूरत में मोहम्मद यूनुस को भारत के कड़े रुख का सामना करना पड़ सकता है। यह न भूलें कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को चलाने में भारत का बहुत बड़ा योगदान है। ढाका की बड़ी-बड़ी इमारतों से लेकर दूर-दराज के कच्चे मकानों में जरूरत का काफी सामान भारत से ही जाता है। अगर भारत सहयोग न करता तो बांग्लादेश में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की क्या स्थिति होती? कई बांग्लादेशी अपना इलाज कराने के लिए भारत आते हैं। क्या चीन उनके लिए दरवाजे खोलेगा? यूनुस की आपत्तिजनक टिप्पणियों के जवाब में भारतीय नेताओं ने जिस तरह एकजुटता दिखाई, वह सराहनीय है। राजनीतिक मामलों में भले ही मतभेद रहें, लेकिन राष्ट्रहित के हर बिंदु पर हमें एकजुट होना ही चाहिए।

ट्वीटर टॉक

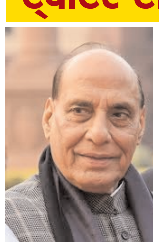

जिस तरह से हर व्यक्ति या वस्तु का कुछ न कुछ स्वभाव होता है, वैसे ही देश का भी अपना एक चरित्र और पहचान होती है। भारत का चरित्र हमेशा आध्यात्मिकता और मानवता की सेवा का रहा है और हमें इस पहचान को हमेशा बनाए रखना है।

-राजनाथ सिंह

राजस्थान के बाड़मेर जिले की बुढ़ातला ग्राम पंचायत में माता जी निर्विरोध सरपंच निर्वाचित हुईं, तो विदेश में रह रहे उनके सुपुत्रों ने 1.25 करोड़ रुपये का निवेश करके ग्राम पंचायत भवन का निर्माण करवाया, जिससे पूरे गांव की कायापलट हो गई।

-मदन दिलावर

प्रेरक प्रसंग

जो होता है अच्छे के लिए होता है

एक राजा अपने मंत्री के साथ आखेट पर निकले। वन में हिरन को देख राजा ने तीर प्रत्यंचा पर चढ़ाया ही था कि जंगल में से एक सूअर निकला और राजा को धक्का देकर भागा। इस अप्रत्याशित आघात के कारण तीर की नोक से उनकी उंगली कट गई। रक्त बहने लगा और राजा व्याकुल हो उठे। राजा की उंगली से खून बहता देखकर मंत्री बोले- 'राजन! भगवान जो करता है, अच्छे के लिए करता है। राजा काफी पीड़ा में थे। मंत्री की बात सुनकर क्रोध से भर उठे। उन्होंने मंत्री को आज्ञा दी कि वो उसी समय उनका साथ छोड़ अन्य राह पकड़ लें। मंत्री ने आदेश को सहर्ष स्वीकार किया और भिन्न दिशा में निकल पड़े। इधर राजा थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि उन्हें जंगल में नरभक्षी कबीले के लोगों ने घेर लिया। वे उन्हें पकड़कर अपने सरदार के पास ले चले। राजा को बलि देने की तैयारी हो ही रही थी कि कबीले के पुजारी ने राजा की कटी उंगली देखकर कहा कि इसका तो अंग भंग है, इसकी बलि स्वीकार नहीं हो सकती।

राजा को जीवनदान मिला तो उन्हें तुरंत मंत्री की याद आई। सोचने लगे कि मंत्री ठीक कहते थे - भगवान जो करता है, अच्छे के लिए ही करता है। मुझे उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए था । ऐसा सोचते वे आगे बढ़ रहे थे कि उन्हें मंत्री नदी किनारे भजन करते दिखाई पड़े। राजा ने प्रेमपूर्वक मंत्री को गले लगाया और उन्हें सारा घटनाक्रम कह सुनाया। इसके बाद राजा ने उनसे प्रश्न किया- मेरी उंगली कटी, इसमें भगवान ने मेरा भला किया, पर तुम्हें मैंने अपमानित करके भगाया, इससे भला तुम्हारा क्या भला हुआ ? मंत्री मुस्कराए और बोले - राजन ! यदि आपने मुझे भिन्न राह पर न भेजा होता और मैं आपके साथ होता तो अंग भंग के कारण नरभक्षी आपकी बलि न देते, पर मेरी बलि चढ़नी सुनिश्चित थी। इसलिए भगवान जो करते हैं, अच्छा ही करते हैं।

सामयिक

'घिब्ली' की दुनिया बनाम हकीकत : कला, रोजगार और मौलिकता का संघर्ष

प्रियंका सौरभ
मोबाइल : 7015375570

घिब्ली का जादू खूबसूरत है, लेकिन अगर यह हमारी असली ज़िंदगी को प्रभावित करने लगे, तो नुकसान हो सकता है। बैलेंस बनाना ज़रूरी है-कला और करियर, कल्पना और हकीकत के बीच! घिब्ली-प्रेरित कला को करियर में बदला जा सकता है-डिजिटल आर्ट, मर्चेंडाइज़, यू ट्यूब कंटेंट और एनिमेशन इंडस्ट्री में इसका उपयोग हो सकता है। लेकिन सिर्फ घिब्ली की दुनिया में खो जाना नुकसानदेह हो सकता है-यह समय की बर्बादी, करियर पर असर, असली दुनिया से डिस्कनेक्ट और मौलिकता की कमी ला सकता है।

अगर हम हकीकत की दुनिया में देखें, तो रोज़गार ज़रूरी है। बिना नौकरी या व्यवसाय के, सिर्फ घिब्ली की खूबसूरत दुनिया में खोकर पेट नहीं भरा जा सकता। लेकिन मानसिक शांति और प्रेरणा के लिए कला भी आवश्यक है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर घिब्ली स्टाइल की इमेज और वीडियो एक ट्रेंड बन चुके हैं। लोग पिनटेरेस्ट, इंस्टाग्राम और टिकटोक पर इसे देखकर टाइम पास कर रहे हैं, कुछ इसे खुद ट्राई कर रहे हैं, और एआई टूल्स की मदद से घिब्ली-स्टाइल की इमेज बना रहे हैं।

आजकल सोशल मीडिया पर घिब्ली स्टाइल इमेज और वीडियो बहुत लोकप्रिय हो गए हैं। एआई टूल्स की मदद से अब कोई भी बिना आर्ट स्किल्स के घिब्ली जैसी इमेज बना सकता है। लोग पिनटेरेस्ट और इंस्टाग्राम पर घिब्ली मूवी के सीन से बनी एस्थेटिक गिफ्स और वॉलपेपर शेयर कर रहे हैं। टिकटोक और रील्स में घिब्ली सीन के साथ रिलेटेबल ऑडियो या कोट्स लगाकर मज़ेदार कंटेंट बनाया जा रहा है। कुछ एआई टूल्स अब आपकी असली फोटो को भी घिब्ली स्टाइल में बदल सकते हैं, जिससे लोग अपनी तस्वीरों को फेयरीटेल लुक दे रहे हैं। यह ट्रेंड सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक बड़ी बहस को जन्म दे रहा है-क्या एआई जनरेटेड आर्ट असली कला की जगह ले सकती है?

एआई-जनरेटेड घिब्ली स्टाइल इमेजरी ने मौलिकता पर सवाल खड़ा कर दिया है। पहले कलाकारों को महीनों मेहनत करके घिब्ली जैसी पेंटिंग बनानी पड़ती थी, अब एआई कुछ सेकंड में वैसा ही कुछ तैयार कर देता है। लोग खुद से नया सोचने के बजाय रेडीमेड आर्ट पर निर्भर हो रहे हैं। असली कलाकार अब एआई-जेनरेटेड कंटेंट से मुकाबला करने को मजबूर हैं। एआई और टेम्प्लेट्स के चलते कुछ हटकर करने की सोच धीरे-धीरे खत्म हो रही है। अगर आर्ट को केवल एक ट्रेंड बना दिया गया, तो मौलिकता धीरे-धीरे खत्म हो जाएगी। इसका समाधान यह है कि लोग घिब्ली स्टाइल से प्रेरणा लेकर अपनी खुद की यूनिक कहानियाँ और आर्ट बनाएं, न कि बस इंटरनेट पर मौजूद चीज़ों को दोहराएँ। घिब्ली की आत्मा सिर्फ उसकी खूबसूरत विज़ुअल्स में नहीं, बल्कि उसकी गहरी कहानियों और भावनात्मक जुड़ाव में है।

अगर किसी को घिब्ली की दुनिया इतनी पसंद है कि वह इसमें कुछ नया जोड़ना चाहता है, तो यह एक रोजगार का साधन भी बन सकता है। उदाहरण के लिए डिजिटल आर्टिस्ट घिब्ली-स्टाइल आर्ट बनाकर पैसा कमा सकते हैं। मर्चेंडाइज़ बिज़नेस (पोस्टर, स्टिकर, कपड़े) से आय हो सकती है। धीर्ढीलश और सोशल मीडिया पर घिब्ली स्टाइल कंटेंट क्रिएट करना एक करियर विकल्प हो सकता है। एनिमेशन इंडस्ट्री में घिब्ली से प्रेरित होकर ओरिजिनल शॉर्ट फिल्म्स और सीरीज़ बनाई जा सकती हैं। गेम डिज़ाइन और वीएफएक्स स्टूडियो में भी घिब्ली जैसी विज़ुअल स्टाइल को अपनाकर कैरियर बनाया जा सकता है। हालांकि, केवल घिब्ली की दुनिया में खोए रहना नुकसानदायक हो सकता है। असली ज़िंदगी के काम टलते रहते हैं, और लोग प्रोडक्टिविटी खो सकते हैं। अगर कोई सिर्फ एनीमेशन देखने में उलझा रहता है और अपने करियर पर ध्यान नहीं देता, तो यह एक समस्या बन सकती है।

घिब्ली की दुनिया आदर्शहोती है-जहाँ हर चीज़ खूबसूरत, शांत और जादुई होती है। लेकिन असली दुनिया संघर्ष, तनाव और कठिनाइयों से भरी होती है। अगर कोई हर समय घिब्ली जैसी ज़िंदगी ढूंढे, तो असली दुनिया बेरंग और कठिन लग सकती है। समय की बर्बादी: लोग घंटों तक घिब्ली मूवीज़, पिनटेरेस्ट आर्ट, एआई -जनरेटेड इमेज और इंस्टाग्राम रील्स देखते रहते हैं। यह टाइम पास कब टाइम वेस्ट में बदल जाता है, पता भी नहीं चलता। अगर कोई सिर्फ एनीमेशन देखने में उलझा रहता है, लेकिन उसे अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए, तो यह नुकसानदेह हो सकता है।

अगर कोई हर समय घिब्ली जैसी ज़िंदगी ढूंढे, तो असली दुनिया बेरंग और कठिन लग सकती है। कुछ लोग इस वजह से प्रेरणा और महत्वाकांक्षा भी खो सकते हैं। घिब्ली स्टाइल इतना लोकप्रिय हो गया है कि कई कलाकार अपनी खुद की स्टाइल डिवेलप करने के बजाय सिर्फ घिब्ली-स्टाइल आर्ट कॉपी कर रहे हैं। घिब्ली स्टाइल एन्जॉय करें, लेकिन उसमें खो न जाएँ। अगर आपको आर्ट पसंद है, तो इसे एक स्किल में बदलें, जिससे आप कमाई कर सकें। अपने करियर और लाइफ गोल्स को इग्नोर न करें-काम ज़रूरी है, कला सिर्फ सुकून के लिए है। मौलिकता बनाए रखें-घिब्ली से प्रेरित हों, लेकिन अपनी खुद की यूनिक स्टाइल डेवलप करें। टाइम मैनेजमेंट करें-आर्ट और मनोरंजन का आनंद लें, लेकिन काम और ज़िम्मेदारियों को नज़रअंदाज़ न करें।

घिब्ली का जादू खूबसूरत है, लेकिन अगर यह हमारी असली ज़िंदगी को प्रभावित करने लगे, तो नुकसान हो सकता है। बैलेंस बनाना ज़रूरी है-कला और करियर, कल्पना और हकीकत के बीच! घिब्ली-प्रेरित कला को करियर में बदला जा सकता है-डिजिटल आर्ट, मर्चेंडाइज़, यू ट्यूब कंटेंट और एनिमेशन इंडस्ट्री में इसका उपयोग हो सकता है। लेकिन सिर्फ घिब्ली की दुनिया में खो जाना नुकसानदेह हो सकता है-यह समय की बर्बादी, करियर पर असर, असली दुनिया से डिस्कनेक्ट और मौलिकता की कमी ला सकता है। समाधान यह है कि घिब्ली की प्रेरणा से कुछ नया और मौलिक बनाया जाए, न कि केवल कॉपी किया जाए। कला और रोजगार के बीच संतुलन बनाए रखना ज़रूरी है ताकि हम जीवन के दोनों पहलुओं का पूरा लाभ उठा सकें।

ज्ञान विज्ञान

सिर्फ 11 हजार में होगा कैंसर का इलाज, चीन ने बनाई नई थेरेपी

कैंसर एक जानलेवा बीमारी है, जिसका इलाज अभी भी महंगा और लंबा होता है। मगर अब कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी का इलाज महज 11 हजार रुपये में हो सकता है। चीनी वैज्ञानिकों ने एक नई तकनीक विकसित की है। जिसे 'ऑन्कोलाइटिक वायरस थेरेपी' कहा जाता है। यह तकनीक न केवल कैंसर के खतरनाक ट्यूमर को खत्म करने की क्षमता रखती है, बल्कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को भी सक्रिय कर सकती है। ऑन्कोलाइटिक वायरस को एक छिपे हुए हत्यारे के रूप में देखा जा सकता है। वैज्ञानिकों ने इन वायरस को इस तरह से विकसित किया है कि वे सीधे कैंसर कोशिकाओं में प्रवेश करें, वहां अपनी संख्या बढ़ाएं और अंततः कैंसर कोशिकाओं को नष्ट कर दें। इतना ही नहीं, ये वायरस ऐसे प्रोटीन भी छोड़ सकते हैं जो शरीर की प्रतिरोधक प्रणाली को बाकी बची हुई कैंसर कोशिकाओं को खत्म करते हैं।

यह तकनीक कोई नई नहीं है। ऑन्कोलाइटिक वायरस पर शोध करीब 100 साल पहले शुरू हुआ था, लेकिन हाल के वर्षों में जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से इसकी क्षमता में जबरदस्त सुधार हुआ है। अब तक, अमेरिका और जापान समेत दुनिया के कुछ देशों में इस तकनीक को अपनाया गया है, लेकिन चीन इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहां करीब 60 क्लीनिकल ट्रायल चल रहे हैं, जिनसे उम्मीद की जा रही है कि यह इलाज आम लोगों के लिए सुलभ और किफायती हो सकेगा। इस साल जनवरी में प्रकाशित एक शोध में 58 वर्षीय महिला की कहानी सामने आई, जिसे सर्वाइकल कैंसर था और सभी पारंपरिक इलाज बेअसर हो चुके थे। उसे ऑन्कोलाइटिक वायरस थेरेपी दी गई और नतीजा यह हुआ कि उसके मेटास्टैटिक ट्यूमर पूरी तरह से गायब हो गए। हैरानी की बात यह है कि इस थेरेपी के बाद महिला 36 महीने तक जिंदा रही। यह शोध दक्षिण चीन के ग्वांगशी मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर झाओ योंगशियांग के नेतृत्व में किया गया था। वैज्ञानिकों ने एक ऐसे वायरस का इस्तेमाल किया जिसने कैंसर कोशिकाओं को सुअर के ऊतक जैसा बना दिया, जिससे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली ने उन्हें बाहरी तत्व मानकर नष्ट कर दिया। इस छोटी ट्रायल में यह भी देखा गया कि 90% मरीजों (जिन्हें लिवर, ओवेरियन और लंग कैंसर था) में ट्यूमर का आकार घट गया या स्थिर हो गया। ऑन्कोलाइटिक वायरस थेरेपी की सबसे बड़ी खासियत इसकी कम लागत है। कैंसर के इलाज में अब तक इस्तेमाल की जाने वाली उ-ठ-ढ थेरेपी की कीमत चीन में करीब 1।16 करोड़ रुपये (140,000 अमेरिकी डॉलर) प्रति डोज होती है, इसके मुकाबले, ऑन्कोलाइटिक वायरस थेरेपी का एक इंजेक्शन महज 11 हजार रुपये (140 अमेरिकी डॉलर) में उपलब्ध हो सकता है, सालभर की इस थेरेपी की कुल लागत 3।3 लाख रुपये (4,200 अमेरिकी डॉलर) तक हो सकती है, जो मौजूदा कैंसर उपचार की तुलना में काफी किफायती है।

नजरिया

बांग्लादेश में आग से खेल रहे हैं नए रहनुमा

बाल मुकुन्द ओझा
मोबाइल : 9414441218

भारत के शत्रु देशों में चीन और पाकिस्तान के बाद अब बांग्ला देश भी शामिल हो गया है जो हमारे लिए बेहद चिंता का विषय है। जिस देश को हमने आज़ादी दिलाई, वह आज हमारे दुश्मन देशों से हाथ मिला रहा है। एक ताज़ा मीडिया रिपोर्ट मुताबिक, शेख हसीना का जोर जबरिया तख्ता पलट के बाद बांग्ला देश के नये रहनुमा बांग्लादेश के निर्माण में अपना सर्वाधिक योगदान देने वाले और खून पसीना बहाने वाले भारत को आंख दिखाने का दु:साहस कर रहे है। यह सर्व विदित है 1971 में जब बांग्लादेश डूब रहा था तो भारत ने अपना पैसे, हथियार और सैनिक दांव पर लगाकर उसकी रक्षा की और आजादी दिलाई। चीन दौरे पर गए बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने भारत के सात लैंड लॉक्ड राज्यों का हवाला दिया और ढाका को इस पूरे क्षेत्र में मौजूद समुद्र का एकमात्र गार्जियन बताते हुए चीन से अपने देश में निवेश का प्रस्ताव दिया। यूनुस ने अपने देश के व्यापार की चर्चा करने के बजाय उन मुद्दों को उभारा जो उनकी नजर में इस क्षेत्र में भारत की कमजोरी है।

बांग्ला देश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख़ हसीना के भारत में शरण लेने के बाद भारत और बांग्ला देश के रिश्तों में कड़वाहट आयी है। बांग्लादेश सरकार ने भारत से शेख़ हसीना के प्रत्यर्पण का अनुरोध किया है। दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण समझौता होने के बावजूद भारत ने बांग्लादेश के इस अनुरोध पर

अब तक कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया है। इसी बीच चीन और पाकिस्तान जैसे भारत के कथित शत्रु देशों ने बांग्ला देश पर अपना शिंकजा कसना शुरू कर दिया। बांग्ला देश धीरे धीरे भारत विरोधी ताकतों के चंगुल में फंसता जा रहा है। शेख हसीना सरकार को गिराने के बाद कट्टरपंथियों के हौसले बुलंद है। अगस्त में जबसे शेख हसीना सरकार का तख्तापलट हुआ, तब से भारत विरोधी ताकतों ने कब्जा जमाया है। मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाला बांग्लादेश भारत को आंख दिखा रहा है। वहां से भारत के खिलाफ बयान दिए जा रहे हैं। वहीं पाकिस्तान और चीन से अच्छे ताल्लुकात बनाए जा रहे हैं। शेख हसीना के खिलाफ वहां चले आंदोलन को पाकिस्तान का पूरा समर्थन हासिल था। इस आंदोलन में छात्रों के साथ, वहां की दक्षिणपंथी पार्टी बीएनपी के सदस्य भी थे। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने मुस्लिम कट्टरपंथी संगठन जमात-ए-इस्लामी पर लगी पाबंदी हटा दी है।

निर्वाचित सरकार को गिराने के बाद कट्टरपंथी ताकतों ने खुलेआम हिन्दुओं और उनके पूजा स्थलों पर हमले शुरू कर दिए है। ये मामले पड़ोसी देश में शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग सरकार के गिरने के बाद सामने आए हैं। इससे उनके खतरनाक इरादों का पत्ता चलता है।

पाकिस्तान और बांग्ला देश में जब भी कोई सियासी घटनाक्रम होता है उस दौरान उपद्रवी कट्टरपंथी तत्व अल्पसंख्यकों पर सबसे पहले हमले शुरू कर देते है। दोनों मुस्लिम देशों में हिंदू आबादी हमेशा निशाने पर रही है। यही वजह है कि वहां साल-दर-साल हिंदुओं की आबादी घटती जा रही है। विशेषकर हिन्दू और हिन्दू मंदिर उनके निशाने पर होते है। अल्पसंख्यकों की जिंदगी पाकिस्तान और बांलादेश दोनों में नर्क है। यहां पर आए दिन हिंदू परिवारों के साथ उत्पीड़न का मामला आता रहता है। हिंदूओं को जबरन इस्लाम कबूल करने पर मजबूर किया जाता है। हिंदू बेटियों का धर्म परिवर्तन कर जबरन मुस्लिम पुरुषों से निकाह कराया जाता है। आए दिन हिंदू लड़कियों के साथ रेप के मामले सामने आते रहते हैं। विभाजन के समय पाकिस्तान में 23 प्रतिशत हिंदू-सिख थे आज घटकर 2 प्रतिशत बचे हैं।

बांग्लादेश में भी अब पाकिस्तान जैसे हालात उत्पन्न होते जा रहे हैं। एक स्टडीज के मुताबिक बांग्ला देश में 1951 में हिंदुओं की आबादी 23 प्रतिशत थी, जो 2017 में घटकर 9 फीसदी रह गई। अब तो ओर भी कम हो गई है। बांग्लादेश मानवाधिकार संगठन ऐन ओ सलीश केंद्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 2013 से 2021 तक बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाते हुए 3600 हमले हुए। इस दौरान हिंदू महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न के कई मामले भी सामने आए। एक आंकड़े के मुताबिक बीते समय बांग्लादेश में 150 से अधिक हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया गया था। इस स्टडी के अनुसार, इन 10 वर्षों के दौरान हिंदुओं के खिलाफ हमलों में एक हज़ार से अधिक घरों और 600 दुकानों और व्यवसायों को निशाना बनाया गया और उनमें तोड़फोड़ और आगजनी की गई। इस दौरान हिंदू मंदिरों, मूर्तियों और पूजा स्थलों में तोड़फोड़ और आगजनी के दो हज़ार से अधिक मामले दर्ज किए गए।

महत्त्वपूर्ण
Published by Bhupendra Kumar on behalf of New Media Company, Arihant Plaza, 2nd Floor, 84-85, Wall Tax Road, Chennai-600 003 and printed by R. Kannan Adityan at Deviyin Kanmani Achagam, 246, Anna Salai, Thousand Lights, Chennai-600 006. Editor : Bhupendra Kumar (Responsible for selection of news under PRB Act.). Group Editor - Shreekant Parashar. Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any suchmanner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.Regn No.RNI No. : TNHIN / 2013 / 52520

पाठकों से अनुरोध है कि इस प्रकाशन में प्रकाशित किए जाने वाले किसी भी तरह के विज्ञापन (वैवाहिक, वर्गीकृत, टैंड़र एवं सजावटी इत्यादि) पर कोई भी कार्यवाही, प्रतिबद्धता या धनराशि का व्यय करने से पूर्व इन विज्ञापनों के बारे में समस्त जानकारी वह स्वयं प्राप्त कर लें। दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह उत्पादों की गुणवत्ता तथा सेवाओं के लिए विज्ञापनदाताओं द्वारा किए जा रहे किसी प्रकार के दावों के लिए जिम्मेदार नहीं है। अगर विज्ञापनदाता विज्ञापन में किया जा रहा दावा पूरा नहीं करता है तो दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह के संपादक, मुद्रक एवं प्रकाशक या मालिकान को पाठक किसी भी रूप में उत्तरदाई नहीं बना सकता।- दक्षिण भारत राष्ट्रमत

रैली

भाजपा नेता और पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी भाजयुमो कार्यकर्ताओं के साथ बुधवार को कोलकाता में पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एक प्रतिनिधिमंडल सौंपने के लिए 'टीएमसी से हिंदू मतदाता बचाओ' रैली में भाग लेते हुए।

म्यांमार में भूकंप के बाद मलबे में फंसे व्यक्ति को जीवित बाहर निकाला गया

बैंकॉक/एपी। म्यांमार में भूकंप के बाद राहत एवं बचाव कार्य में जुटे बचाव दल ने बुधवार सुबह राजधानी नेपीता के उस होटल के मलबे से 26 वर्षीय एक व्यक्ति को जीवित बाहर निकाला, जहां वह काम करता था। हालांकि, देश में आए भीषण भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़ने की ही आशंका है क्योंकि भूकंप के पांच दिन बाद भी अधिकतर बचाव दल को केवल शव ही मिल रहे हैं।

मलबे में नाइंग लिन टुन के स्थान को सटीक रूप से निर्धारित करने और उसके जीवित होने की पुष्टि करने के लिए एक 'एंडिस्कोपिक कैमरे' का उपयोग किया गया था। व्यक्ति को सावधानीपूर्वक फर्श में छेद करके बाहर निकाला गया। व्यक्ति भूकंप के बाद लगभग 108 घंटे उस होटल में फंसा रहा जहां वह काम करता था। स्थानीय अग्निशमन विभाग द्वारा जारी किए गए वीडियो में नैंग लिन टुन कमजोर लेकिन होश में नजर आ रहा था। सरकारी एमआरटीवी' ने बताया कि नेपीता शहर में बचाव कार्य तुर्किये और स्थानीय टीम द्वारा किया गया और इसमें नौ घंटे से अधिक का समय लगा। म्यांमार में शुक्रवार दोपहर को 7.7 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके कारण हजारों इमारतें ढह गईं, पुल ध्वस्त हो गए और सड़कें उखड़ गईं। अब तक 2,719 लोगों की मौत हो चुकी है और 4,521 लोग घायल हुए हैं, लेकिन स्थानीय खबरों में यह आंकड़ा कहीं अधिक बताया जा रहा है।

मनसे पाकिस्तानी अभिनेता फवाद खान अभिनीत फिल्म 'अबीर गुलाल' की रिलीज का विरोध करेगी

मुंबई। राज ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) ने बुधवार को कहा कि वह पाकिस्तानी अभिनेता फवाद खान की फिल्म अबीर गुलाल' की रिलीज का विरोध करेगी। मनसे की सिनेमा शाखा के अध्यक्ष अमिय खोपकर ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि कई बार यह कहने के बावजूद कि पार्टी पाकिस्तानी अभिनेताओं वाली फिल्मों को भारत में रिलीज नहीं होने देगी, कुछ 'निराशाजनक घटनाएं' सामने आती रहती हैं। खोपकर ने कहा, हम महाराष्ट्र में 'अबीर गुलाल' की रिलीज नहीं होने देंगे। जो लोग पाकिस्तानी अभिनेताओं को खुश करना चाहते हैं, वे ऐसा कर सकते हैं लेकिन उन्हें हमसे निपटना होगा। खान और वाणी कपूर अभिनीत 'अबीर गुलाल' नौ मई को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। 'चलती रहे जिंदगी' फिल्म की निर्देशक आरती एस. बागड़ी द्वारा निर्देशित इस फिल्म का निर्माण 'इंडियन स्टोरीज', 'ए रिचर लेंस' और 'आरजय पिक्चर्स' ने किया है। निर्माताओं ने मंगलवार को फिल्म की रिलीज की तारीख की घोषणा करते हुए एक टीजर जारी किया।

'टॉप गन', 'बैटमैन' के अभिनेता वैल किल्मर का निधन

लॉस एंजिलिस/एपी। 'टॉप गन' में आईसमैन का किरदार निभाकर दर्शकों के चहेते बने अभिनेता वैल किल्मर का निधन हो गया। वह 65 वर्ष के थे। अभिनेता ने बैटमैन 'फॉरएवर' में बैटमैन का किरदार निभाया था और 'द डोर्स' में उन्होंने जिम मॉरिसन के किरदार को जीवंत किया था। किल्मर की बेटी मर्सिडीज किल्मर ने 'एसोसिएटेड प्रेस' (एपी) को एक ईमेल में बताया कि मंगलवार रात लॉस एंजिलिस में उनका निधन हुआ। इस दौरान उनके परिवार के सदस्य उनके साथ थे। किल्मर निमोनिया से पीड़ित थे। 2014 में गले के कैंसर के निदान के बाद वह ठीक हो गए थे। उन्होंने 1984 में जासूसी फिल्म 'टॉप सीक्रेट' से शुरुआत की, उसके बाद 1985 में हास्य फिल्म 'रियल जीनियस' में काम किया। बाद में किल्मर ने 'मैकग्रुबर' और 'किस किस बैंग बैंग' जैसी फिल्मों में फिर से अपनी कॉमेडी का जलवा दिखाया।

हसीना की अवामी लीग के एक लाख से अधिक सदस्य भारत भागे

ढाका/भाषा। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सूचना सलाहकार महफूज आलम ने मंगलवार को दावा किया कि अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी के एक लाख से अधिक सदस्य भारत भाग गए हैं। मीडिया में आलम का यह बयान आया। बांग्लादेशी समाचार पोर्टल बीडीन्यूज24डॉट कॉम के अनुसार, आलम ने यह टिप्पणी यहां ईद के अवसर पर आयोजित एक समारोह में की, जिसमें हसीना के कार्यकाल के दौरान कथित रूप से लापता या मारे गए व्यक्तियों के परिवार शामिल हुए थे।

उत्सव

ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी बुधवार को भुवनेश्वर के बड़ागढ़ गांव विद्यालय में 'प्रभु उत्सव', 'खड़ीछुआ' और 'शिशु बाटिका' के राज्य स्तरीय शुभारंभ के दौरान बच्चों से बातचीत करते हुए।

पाकिस्तान के राष्ट्रपति की तबीयत बिगड़ी, कराची के अस्पताल में भर्ती

कराची/भाषा। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें कराची के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 'द एक्सप्रेस ट्रिब्यून' में मंगलवार को प्रकाशित खबर में बताया गया है कि 69 वर्षीय जरदारी को बुखार और संक्रमण की शिकायत के बाद कराची से करीब 300 किलोमीटर दूर नवाबशाह से शहर के एक अस्पताल लाया गया। खबर के मुताबिक, जरदारी की कई चिकित्सीय जांच की गई और डॉक्टर उनकी स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं।

स्थानीय मीडिया की खबर के अनुसार, जरदारी सोमवार को ईद की नमाज अदा करने के लिए नवाबशाह गए थे और इससे पहले रविवार को उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की थी। पाकिस्तान की सरकारी समाचार एजेंसी 'एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान' (एपीपी) ने मंगलवार को बताया कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने टेलीफोन पर राष्ट्रपति जरदारी के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।

राशि खन्ना ने अपनी एनर्जेटिक जिम रूटीन से फिटनेस को बनाया मजेदार!

मुंबई/एजेन्सी

कौन कहता है कि वर्कआउट सिर्फ पसीना बहाने और थकने का नाम है? पैन-इंडिया स्टार राशि खन्ना फिटनेस को एक नया रूप दे रही हैं, जहां मेहनत और मस्ती का अनोखा मेल देखने को मिल रहा है! अपनी सीमाओं को लगातार आगे बढ़ाने वाली राशि इन दिनों जिम में पहले से ज्यादा मेहनत कर रही हैं, लेकिन उनके वर्कआउट सेशन्स में सिर्फ इंटेंस एक्सरसाइज़ ही नहीं, बल्कि ढेर सारी मस्ती और जोश भी शामिल है। अपनी हालिया सोशल मीडिया पोस्ट में, राशि एकदम बीस्ट मोड में नजर आ रही हैंवेट लिफ्टिंग, एगिलिटी ड्रिल्स और जबरदस्त वर्कआउट कर रही है। लेकिन जो चीज़ उनकी रूटीन को सबसे ज्यादा प्रेरणादायक बनाती है, वो है उनकी इंफेक्शियस एनर्जी और चुलबुला अंदाज। एक्सरसाइज़ के बीच-बीच में वह अपने ट्रेनर के

साथ मजेदार पल भी शेयर कर रही हैं, यह साबित करते हुए कि मेहनत और मस्ती एक साथ चल सकते हैं। उन्होंने इस पोस्ट के साथ लिखा, एवरी डे, आई शो अप। एवरी डे, आई कम्प्लेन। एवरी डे, आई सर्वाइव। रिलेटेबल?

राशि के फिटनेस सफर की यह झलक प्रशंसकों को काफी पसंद आ रही है, लोग उनकी मेहनत और पॉजिटिव एनर्जी की तारीफ कर रहे हैं। 'द साबरमती रिपोर्ट' में अपने दमदार किरदार से सबका दिल जीतने वाली राशि आज की सबसे प्रतिभाशाली पैन-इंडिया स्टार्स में से एक मानी जाती हैं और वह स्क्रीन के अंदर और बाहर, दोनों जगह अपने फैंस को लगातार प्रभावित कर रही हैं। राशि ने हाल ही में इस साल के लिए कुछ रोमांचक प्रोजेक्ट्स की ओर इशारा किया है, हालांकि अभी तक ज्यादा डिटेल्स सामने नहीं आई हैं। इसके अलावा, उन्हें एक्सेल एंटरटेनमेंट के ऑफिस में स्पॉट किया गया, जिससे फैंस के बीच उनके अगले प्रोजेक्ट को लेकर एक्साइटमेंट और भी बढ़ गई है। फिटनेस, मस्ती और प्रोफेशनल सफलता को बैलेंस करते हुए राशि खन्ना लगातार यह साबित कर रही हैं कि वह इंडस्ट्री की सबसे शानदार और दमदार कलाकारों में से एक हैं!

'आशिकी 3' टीम ने की प्रेम सिंह तमांग से मुलाकात

गंगटोक/एजेन्सी

सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने अपने आवास पर फिल्म निर्माता-निर्देशक अनुराग बसु, अभिनेता कार्तिक आर्यन और श्रीलीला से मुलाकात की। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। अपकमिंग फिल्म 'आशिकी 3' की टीम एक सप्ताह से सिक्किम में है और राज्य भर में कई खूबसूरत स्थानों पर फिल्म की शूटिंग चल रही है। बैठक के दौरान, मुख्यमंत्री ने टीम को शुभकामनाएं दीं और सिक्किम को फिल्मांकन स्थल के रूप में चुनने के लिए आभार जताया। उन्होंने कलाकारों को पारंपरिक उपहार भी भेंट किए।

इसके साथ ही, सीएम तमांग ने उनके प्रोजेक्ट के लिए राज्य सरकार की ओर से निरंतर समर्थन का आश्वासन भी दिया। अपनी टीम की ओर से आभार व्यक्त करते हुए, बसु ने मुख्यमंत्री को उनके

प्रोत्साहन और सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने सिक्किम में कई स्थानों पर फिल्म की शूटिंग करने की अनुमति देने के लिए राज्य सरकार की सराहना भी की। गंगटोक और आस-पास के इलाकों में शूटिंग कर रहे अभिनेता कार्तिक आर्यन के सिक्किम में प्रशंसकों का बड़ा वर्ग देखने को मिला। अभिनेता ने लोगों से मिले प्यार और समर्थन पर आभार जताया। कार्तिक ने टीम की सुरक्षा करने के लिए सिक्किम पुलिस को विशेष धन्यवाद दिया, जिससे उन्हें अपना काम सुचारू रूप से पूरा करने में मदद मिली। इस बीच, अभिनेत्री श्रीलीला सिक्किम की खूबसूरती और वहां की परंपराओं से प्रभावित और खूबसूरती में खोई नजर आईं। उन्होंने बताया कि यह उनकी सिक्किम की पहली यात्रा है और वह राज्य की प्राकृतिक सुंदरता से इतनी मंत्रमुग्ध हैं कि उनकी पहली यात्रा यादगार बन गई है। कार्तिक आर्यन, श्रीलीला स्टारर अपकमिंग फिल्म की शूटिंग सिक्किम के खास स्थानों पर चल रही है, जिसमें एमजी मार्ग और त्सोंगमो झील भी शामिल हैं। फिल्म में राज्य के खूबसूरत दृश्यों, संस्कृति और पारंपरिक वास्तुकला दिखने की उम्मीद है, जिससे सिक्किम फिल्म निर्माण के लिए एक प्रमुख गंतव्य के रूप में बढ़ावा मिलेगा।

एम्पुरान विवाद : मोहनलाल स्टारर फिल्म में लगेंगे 24 कट

हैदराबाद/एजेन्सी

सिनेमाघरों में रिलीज के बाद से विवादों में घिरी मलयालम फिल्म 'एम्पुरान' को लेकर सह-निर्माता एंटनी पेरुंबवूर ने मंगलवार को महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने बताया कि विवाद के मद्देनजर फिल्म में 24 कट लगाए जाएंगे। उन्होंने जानकारी दी कि फिलहाल फिल्म के फिर से संपादन में जुटे लोगों ने एक भाग पूरा कर लिया है और दूसरा भाग मंगलवार को शुरू हो जाएगा। बुधवार से री-एडिट फिल्म का वर्जन स्क्रीन पर आने की संभावना है।

बता दें, गर्भवती महिला वाले हिंसक दृश्यों को हटा दिया गया है और खलनायक का नाम बेजरंगी से बदलकर बलदेव कर दिया गया है। केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी के अनुरोध पर फिल्म की धन्यवाद स्लाइड से उनका नाम हटा दिया गया है। फिल्म में प्रमुख जांच एजेंसी एनआईए का गलत तरीके से उल्लेख किया गया है और अब नए वर्जन में उस हिस्से को म्यूट कर दिया गया है। पेरुंबवूर ने स्पष्ट किया कि फिल्म को फिर से संपादित करने का निर्णय पूरी टीम का था। पेरुंबवूर ने कहा, हम गलत विषय पर फिल्म नहीं बनाते। फिल्म को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है और किसी विवाद की कोई आवश्यकता नहीं है। फिल्म में एडिटिंग किसी बाहरी दबाव की वजह से नहीं, बल्कि कुछ दर्शकों

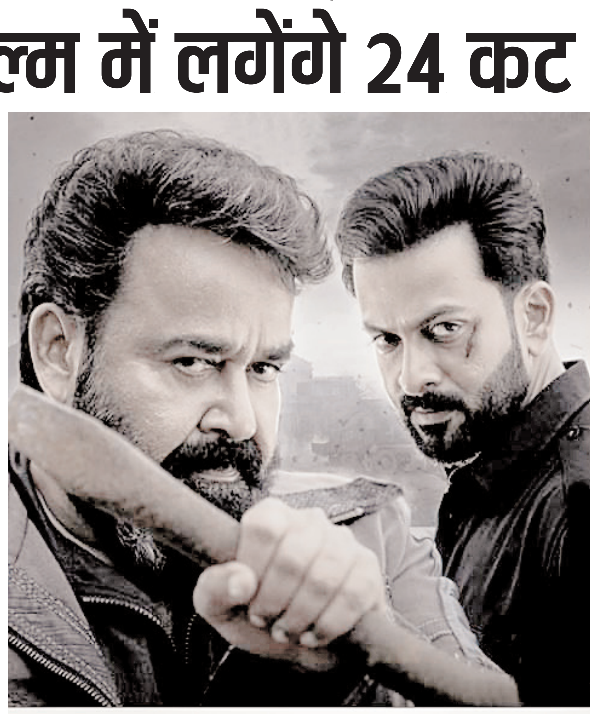

को ध्यान में रखकर किया गया है। उन्होंने कहा, जब हमें लगा कि समाज के कुछ वर्ग नाखुश हैं, तो हमने फिर से विचार करने का फैसला किया और सामूहिक रूप से इस निर्णय पर पहुंचे।

निर्देशक पृथ्वीराज सुकुमारन पर आरोप लगाने की अटकलों को खारिज करते हुए पेरुंबवूर ने कहा कि सुपरस्टार मोहनलाल सहित सभी लोग रचनात्मक निर्णयों से पूरी तरह अवगत थे। उन्होंने स्पष्ट किया, पृथ्वीराज को अलग करने का कोई कारण नहीं है। आरएसएस से जुड़े प्रकाशन 'ऑर्गनाइजर' द्वारा 'एम्पुरान' की आलोचना किए जाने के बाद विवाद शुरू हुआ, जिसने पहले मोहनलाल और बाद में पृथ्वीराज को निशाना बनाया। फिल्म का एडिट वर्जन क्यूब सिनेमा द्वारा संसाधित किया जा रहा है, जो सभी सिनेमाघरों और स्क्रीनिंग केंद्रों में अपडेटेड डिजिटल प्रिंट वितरित करेगा। मंगलवार को केरल उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गई, जिसमें मलयालम फिल्म 'एम्पुरान' की स्क्रीनिंग रोकने की मांग की गई। याचिकाकर्ता ने फिल्म में गोधरा के बाद हुए सांप्रदायिक दंगों के चित्रण पर आपत्ति जताई और कहा कि इससे सांप्रदायिक हिंसा भड़कने का खतरा है।

शबाना आजमी ने बताया, जीवन में अभी और क्या तलाशना बाकी है ?

नई दिल्ली/एजेन्सी

राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता शबाना आजमी का कहना है कि, यह मानना अवास्तविक होगा कि उन्होंने सब कुछ अनुभव कर लिया है। उनके अनुसार, अभी तो पूरा जीवन ही जानना बाकी है। यह पूछे जाने पर कि क्या ऐसा कुछ है जो वह अभी भी नहीं जानती या जिसके बारे में वह जानना चाहती हैं, शबाना ने आईएएनएस को बताया: हां, संपूर्ण जीवन। क्योंकि यह सोचना बेकार है कि मैंने सब कुछ अनुभव कर लिया है। हां, मैं अब ज़्यादा रोमांचक काम नहीं कर सकती। वो बेवकूफी होगी, लेकिन मैं फिर भी करना चाहती हूं। मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। अभिनेत्री ने 1974 में अंकुर से अपनी शुरुआत की थी। शोबिज की दुनिया में पांच दशक बिताने वाली इस अभिनेत्री की फिल्मोग्राफी में 160 से ज्यादा फिल्में शामिल हैं, जिनमें से ज्यादातर स्वतंत्र और नवयथार्थवादी समानांतर सिनेमा की हैं। उन्होंने मुख्यधारा की फिल्मों के साथ-साथ कई अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट भी किए हैं। शबाना विभिन्न विधाओं में विशिष्ट, अक्सर अपरंपरागत महिला किरदारों के लिए लोकप्रिय हैं।

अपने दमदार अभिनय के कारण उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए पांच बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है। अभिनेत्री को 1998 में पद्म श्री और 2012 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। पीछे मुड़कर देखें तो क्या ऐसी कोई भूमिका है जिसे न निभा पाने का उन्हें अफसोस है या कोई ऐसी फिल्म है जिसका हिस्सा आप बनना चाहती थीं? वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक समग्र मंच, अंतरा एजईजी के उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित अभिनेत्री ने कहा अभिनेत्री ने कहा, मेरी एक दोस्त कहती है कि मेरी एक अजीब आदत है। मैं कभी-कभी कहती हूं, 'अच्छा हुआ मैंने वो फिल्म नहीं की।' वो पूछती है, 'क्या तुम्हें वो फिल्म ऑफर हुई थी?' मैं कहती हूं, 'नहीं।' तो वो कहती है, 'फिर तुम क्यों खुश हो?' मेरे दिमाग में एक ख्याल आता है कि अच्छा है कि मैंने वो फिल्म नहीं की, लेकिन जब मुझे वो मिली ही नहीं, तो मैं क्या ही कर लेती? वह दोस्त मेरी इस बात पर हमेशा हंसती है। काम की बात करें तो अभिनेत्री को आखिरी बार आर. बाल्की की स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म घूमर में देखा गया था। इसमें अभिषेक बच्चन, सैयामी खेर और अंगद बेदी भी हैं।

'राहु केतू' की शूटिंग शुरू

मुंबई/एजेन्सी

अभिनेता पुलकित सम्राट अपनी अपकमिंग फिल्म 'राहु केतू' की शूटिंग शुरू कर चुके हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर उन्होंने प्रशंसकों को मजेदार अंदाज में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राहु-केतू सही जगह हैं, क्योंकि तारे भी लाइन पे लग चुके हैं। शेयर की गई तस्वीरों में से एक में वह हाथ में क्लैप बोर्ड पकड़े हुए हैं, तो दूसरी में टीम के साथ फोटो खिंचवाते नजर आए। पोस्ट के साथ अभिनेता ने कैप्शन में लिखा, तारे भी लाइन पे लग गए क्योंकि हमारे राहु-केतू बिल्कुल सही जगह हैं! तैयार हो जाओ, हम तुम्हारी कक्षा में प्रवेश करने वाले हैं! 'राहु केतू' की शूटिंग शुरू, सिनेमाघरों में जल्द मिलते हैं। पुलकित ने इंस्टाग्राम पर अपने प्रोजेक्ट 'राहु केतू' की शूटिंग शुरू होने से पहले कई तस्वीरें और वीडियोज भी शेयर किए। क्लिप में सम्राट टीम के साथ शूटिंग से पहले मुहूर्त पूजा करते नजर आए। उनके साथ वरुण शर्मा और शालिनी पांडे भी दिखे।

उनकी पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए अभिनेत्री कृति खरबंदा ने लिखा, बधाई हो और शुभकामनाएं, आप अद्भुत लोग हैं! जी स्टूडियोज ने सोशल मीडिया पर राहु-केतू के सेट से कुछ तस्वीरें भी साझा कीं और पोस्ट को कैप्शन दिया, कुछ लोग इसे भाग्य कहते हैं, हम इसे राहु-केतू का खेल कहते हैं और ये आपके जीवन में भी जल्द ही प्रवेश करेंगे, शूटिंग अब शुरू होती है। विपुल विग के निर्देशन में बन रही 'राहु-केतू' में पुलकित सम्राट और शालिनी पांडे के साथ वरुण शर्मा भी अहम भूमिका में हैं। सम्राट और वरुण की जोड़ी हिट कॉमेडी 'फुकरे' में साथ काम कर चुकी है, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया। वर्कफ्रंट की बात करें तो 'राहु-केतू' के अलावा, पुलकित सम्राट के पास अभिनेत्री इसाबेल कैफ के साथ 'सुस्वागतम खुशामदीद' भी है। 'सुस्वागतम खुशामदीद' फिल्म में शामिल होने को लेकर उत्साहित अभिनेता पुलकित सम्राट ने बताया कि वह एक अच्छी कहानी और बेहतरीन टीम का हिस्सा बनकर खुश हैं। प्यार, एकता और अपनेपन का संदेश देती फिल्म का निर्देशन धीरज कुमार ने किया है। रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म 16 मई 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

RNI No. : TNHIN/2013/52520
Regn No. : TN/CCN/613/2014-2016
posted at Patrika Channel,
Egmore RMS, Chennai-8

जाति, भाषा, प्रांत और संप्रदायों का भेदभाव इतना जहरीला होता है कि वह न्याय, नीति, मानवता और कर्तव्य का बोध कभी नहीं होने देता। इनके बलबूते पर अयोग्य भी सत्ता की योग्यता प्राप्त कर लेते हैं। नीति शास्त्र कहता है कि अयोग्य के पास आई हुई सत्ता, सामर्थ्य और शक्ति सदैव लोगों के शोषण तथा उत्पीड़न का ही काम करती है। कमोबेश हम अपने देश के अनेक प्रांतों में और विश्व के अनेक देशों में यही स्थिति देख रहे हैं। यह कलयुग की करुण दर्दनाक कथा है।

संस्थापक दिवस पर शिक्षाविद् एवं परोपकारी जयगोपाल गारोदिया के गुणों को किया याद

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। यहां जयगोपाल गारोदिया ग्रुप ऑफ स्कूल्स ने अपने संस्थापक अध्यक्ष जयगोपाल गारोदिया की पंद्रहवीं वर्षगांठ बुधवार को 'संस्थापक दिवस' के रूप में मनाई। इस मौके पर अन्नानगर, कोलाथुर, शक्तिवेल नगर, परुथिपट्ठु और अन्य स्थानों पर जयगोपाल गारोदिया समूह के स्कूलों में विशेष सभाएँ आयोजित की गईं। प्रबंध ट्रस्टी अशोक केडिया, ट्रस्टी मेयप्पन, हितेश कनोड़िया, प्रधानाचार्यों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों द्वारा स्व. जयगोपाल गारोदिया की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। संस्थापक की स्मृति में गरीबों को भोजन कराया गया। प्रबंध ट्रस्टी और ट्रस्टियों ने संस्थापक अध्यक्ष की सेवाओं को याद किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि विद्यार्थियों को विभिन्न स्रोतों से ज्ञान प्राप्त करने के अवसर का सही उपयोग करना चाहिए।

इसी तरह के कार्यक्रम तांबरम, अवाडी, चूलाईमेडु, सैदापेट, नंगनल्लूर, विरुगमबक्कम, तिरुवोट्टियूर, मनाली, माधवरम, पोन्नेरी, मदुरै और बेंगलूरु में स्थित जयगोपाल गारोदिया द्वारा प्रायोजित सरकारी स्कूलों और प्रबंधन स्कूलों में भी आयोजित किए गए थे। अपने जीवनकाल में संस्थापक जयगोपालजी ने महिलाओं की शिक्षा पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कॉलेज के छात्रों के लिए निःशुल्क पुस्तक बैंक और छात्रवृत्ति केंद्र जैसी विशेष योजनाएं बनाई थीं। स्व. गारोदिया एक पशु प्रेमी थे। उन्होंने 'मे आई हेल्प यू पुलिस बूथ' भी प्रायोजित किए थे।

'नवकार महामंत्र सजाओ' प्रतियोगिता 6 अप्रैल को

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। तमिलनाडु में सम्पूर्ण जैन समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला 'चंदन तिलक जैन समाज' सदैव शैक्षणिक, सामाजिक, बौद्धिक, आर्थिक और आध्यात्मिक विकास के लिए प्रयत्नशील रहता है। उसी क्रम में बच्चों की कल्पनाशक्ति को निखारने एवं समाज में छुपी प्रतिभाओं को उभारने के उद्देश्य से 6 अप्रैल को 'नवकार महामंत्र सजाओ' प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। जैन महासंघ के पूर्व अध्यक्ष एवं चंदन तिलक के चेयरमैन सज्ञनराज मेहता ने कहा कि यह प्रतियोगिता अपने आप में अनूठी एवं चेन्नई में सर्वप्रथम बार आयोजित की जा रही है। इसमें बच्चों को अपनी क्रिटीविटी स्किल को बढाने में मदद मिलेगी, साथ ही बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच मिलेगा। कमला सज्ञनराज मेहता परिवार द्वारा प्रायोजित इस। प्रतियोगिता के निर्णायक मण्डल में डॉ. दिलीप धींग, प्रवीण संचेती, सुभद्रा लुणावत शामिल हैं। आयोजकों ने प्रतियोगिता में अधिक से अधिक बच्चों से जुड़ने की अपील की है।

गुणानुवाद सभा में याद किया गया विनयमुनि 'भीम' के गुणों को

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। यहां साहुकारपेट स्थित स्वाध्याय भवन में गत दिनों विनयमुनिजी 'भीम' के महाप्रयाण हो जाने पर उनकी स्मृति में गुणानुवाद सभा का आयोजन किया गया। स्वाध्यायी श्रद्धालुओं द्वारा स्तुति की गई। नरेन्द्र कांकरिया ने विनयमुनिजी भीम के जीवन परिचय पर प्रकाश डाला।

उन्होंने कहा कि ब्रजलालजी म.सा व मधुकरमुनिजी उनके दीक्षा गुरु रहें व सत्रह वर्ष की वय में नोखा चांदावता राजस्थान में दीक्षित ने 53 वर्षो तक संयम साधना की। श्रमण संघ में उपप्रवर्तक पद व सलाहकार पद का बखूबी निर्वहन किया।

सरल स्वभावी संतरत्न ने चेन्नई में साहुकारपेट, आवडी आदि क्षेत्रों में चातुर्मास किए थे। राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश आदि पन्द्रह राज्यों में विहार विचरण चातुर्मास करते हुए जिनशासन की प्रभावना करने वाले सन्त का महाप्रयाण श्रमण संघ सन्तगण व जिनशासन में बडी क्षति हुई हैं।

उपस्थित स्वाध्यायी बन्धुवरों ने चार लोगस्स का ध्यान करते हुए श्रद्धा सुमन रुपी गुणानुवाद किए। धर्मसभा में उच्छबराज गांग, रुपराज सेठिया, वीरेन्द्र कांकरिया, कांतिलाल तातेड़, गौतमचन्द मुणोत, अम्बालाल कर्णावट दीपक श्रीश्रीमाल, बाबू धनपतराज सुराणा, लीलमचन्द बागमार, इंदरचंद कर्णावट की सामायिक परिवेश में उपस्थिति रही। धनपतराज सुराणा ने मांगलिक प्रदान किया।

संस्कृति और संस्कारों की अमूल्य विरासत प्राणों से भी हो प्यारी : आचार्यश्री विमलसागरसूरी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। शहर के बसवनगुड़ी स्थित जिनकुशलसूरी जैन श्वेतांबर दादावाड़ी ट्रस्ट और संघ के तत्वावधान में बुधवार को अभिभावकों और युवाओं के लिए आयोजित विशेष समारोह को संबोधित करते हुए जैनाचार्य विमलसागर सूरीश्वरजी ने कहा कि भारत की नई पीढियां अपनी राष्ट्रभाषा और स्थानीय मातृभाषा भूलती जा रही हैं। पारंपरिक रीति-रिवाजों में लोगों की रुचि समाप्त प्रायः हो गई है। भाषा के साथ-साथ उनके परिधान, खानपान, संस्कार, सब बदलते जा रहे हैं। अपनी नई पीढियां अंग्रेजों की गुलाम बनकर फैशन के नाम पर फटे हुए, बेहूदे और कम कपड़े पहनती जा रही हैं। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक विदेशी व्यंजन खाने के शौक बढ़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्यवर्धक भारतीय भोजन भुलाया जा रहा है। वे अब शराब, हुक्का, गुटखा, धूम्रपान, ड्रग, क्लब संस्कृति, ऑनलाइन गेमिंग और विजातीय मित्रता जैसी बुराईयों में बरबादी के कगार पर पहुंच गई हैं। इनके कारण डिप्रेशन, अपराध और आत्महत्याओं की घटनाओं में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। यह सब देश व समाज के लिये अत्यंत घातक व चिंताजनक विषय है। लोग पशु-पक्षियों और पर्यावरण के संरक्षण की बातें करते हैं और यहां तो भारतीय समाज का भविष्य ही दांव पर लगा है । जब हमारी नई पीढ़ियां जवानी से पहले ही बरबाद हो जाएगी तो पशु-पक्षियों और पर्यावरण को बचाने का औचित्य भी क्या बचेगा ? मेरी बात अप्रिय और अघातजनक है, पर सत्य हैं।

आचार्यश्री विमलसागर सूरीश्वरजी ने कहा कि अपनी संस्कृति और संस्कारों की अमूल्य विरासत प्राणों के तुल्य प्यारी होनी चाहिए। इनका संरक्षण सम्पूर्ण निष्ठाभावना से किया जाना चाहिए। जिनकी संस्कृति और संस्कार सुरक्षित रहते हैं, मात्र उनका ही धर्म और समाज जीवित रहता है। इज़रायल, जर्मनी, जापान, चीन और खाड़ी के देशों को अपनी संस्कृति पर बहुत गर्व है। वे अपने रीति-रिवाज, परिधान, खानपान, भाषा और संस्कारों को सदियों से संभालकर चल रहे हैं। भारत का आधुनिक समाज अपनी संस्कृति और महान संस्कारों को भूलते जा रहा है। हम विदेश की विकृतियों को अपनाते जा रहे हैं। भले ही यह बात सबके गले नहीं उतरेगी, लेकिन यह कठोर सत्य है कि सांस्कृतिक पतन कत्लखानों से भी अधिक खतरनाक होता है। पशु कभी अपनी कत्ल के लिए कतारों में खड़े नहीं होते। भारत का आधुनिक समाज सांस्कृतिक पतन के रूप में अपनी कत्ल के लिए कतारों में खड़ा हैं। जैनाचार्य ने कहा कि घर-घर में आधुनिक व्यवहारिक शिक्षा के साथ-साथ धार्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए। सरकारों को गंदे सिनेमा, सीरियल, ओटीटी, विज्ञापन आदि माध्यमों पर नकेल कसनी चाहिए, तभी बुराइयों पर काबू पाया जा सकता है।

संगठित सामाजिक प्रयास भी सांस्कृतिक पतन को रोकने में कामयाब हो सकते हैं।

गणि पद्मविमलसागरजी, मुनि मलयप्रभसागरजी आदि श्रमणजन और तेजराज मालानी, बाबूलाल भंसाली, कुशलराज गुलेच्छा, रणजीत ललवानी, तेजराज गुलेच्छा, महेंद्र रांका आदि अनेक गणमान्य लोग समारोह में विशेष रूप से उपस्थित थे। अरविंद कोठारी ने संचालन किया। महिला मंडल ने भावपूर्ण गीतिका प्रस्तुत कर कार्यक्रम का समापन किया।

आठवां गणगौर उत्सव सामूहिक रूप से मनाया गया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। संगम सत्संग समिति के आकाश मंडल द्वारा साहुकारपेट भवन में सार्वजानिक रूप से गणगौर महोत्सव मनाया। पहले तीज के दिन सुबह मां गवर और ईशर की पूजा की। मदन मोहन रंगा द्वारा गणेश वंदना की। इनमें मीना सोनी, जगन गुप्ता, नेहा भाटी, पंकज भाटी, रूपाली, अनामिका अग्रवाल, प्रिया शर्मा, कुनाल थानवी ने मां गणगौर की पूजा में भाग लिया।अगले दिन चौथ पर विभिन्न कलाकारों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। माँ गवर्जा और ईशर जी की आरती के कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। अध्यक्ष बसेसरलाल गोकुलका ने सभी का स्वागत किया तथा सभी को गणगौर पर्व की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर बड़ी संख्या श्रद्धालु उपस्थित थे। मंच संचालन कुनाल थानवी ने किया और राकेश मंगल ने धन्यवाद दिया।

राजस्थान की ट्रेन को लेकर प्रवासियों में खुशी की लहर

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। दक्षिण रेलवे से प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार चेन्नई सेन्ट्रल से आगामी 9 अप्रैल से प्रत्येक बुधवार को डॉ एमजीआर चेन्नई सेंट्रल-भगत की कोठी-डॉ एमजीआर चेन्नई सेंट्रल साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है।

ट्रेन संख्या 06157/06158 डॉ एमजीआर चेन्नई सेंट्रल-भगत की कोठी-डॉ एमजीआर चेन्नई सेंट्रल साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन की 13 सेवाएं शुरु होने को लेकर प्रवासियों में काफी प्रसन्नता है।

गर्मी की छुट्टी शुरु होने और राजस्थान में शादी विवाह के मौके के लिए प्रवासियों ने हमेशा सीधी ट्रेन की मांग की है। जिसके समर्थन में जालौर के सांसद लुंबाराम चौधरी समय समय पर दक्षिण से राजस्थान के लिए सीधी ट्रेन सेवाओं की मांग रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से की है।

कुछ समय पहले चेन्नई एयरपोर्ट में बड़ी संख्या में राजस्थानी बंधुओं ने रेल मंत्री वैष्णव से मुलाकात कर उनकी इस समस्या के बारे में बताया था जिसे उन्होंने शीघ्र ही सुलझा लेने की बात कही थी।

ऐसे समय में ग्रीष्मकालीन ट्रेन की सेवाएं प्रवासियों के लिए राहत देगी। समय समय पर इस क्षेत्र में रेल की मांग करने में भाजपा प्रवासी प्रकोष्ठ तमिलनाडु के संगठन मंत्री केसरसिंह गादाणा, भाजपा नेता पवनकुमार, जालम सिंह, डार्विन शर्मा, ओंगल के रविचन्द्र आदि अनेकों ने प्रयास किए हैं। इस ट्रेन के शुरु हो जाने से प्रवासियों में खुशी की लहर है।

गुरुदेव महाश्रमण का आगाज 'सीखें 25 बोल खास' प्रतियोगिता आयोजित

बेंगलूरु/दक्षिण भारत। शहर के तेरापंथ महिला मंडल राजाजीनगर द्वारा मंगलवार को साध्वीश्री संयमलताजी के सान्निध्य में तेरापंथ भवन में गुरुदेव महाश्रमण का आगाज-'सीखें 25 बोल खास' प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आगम के नामों पर आचारांग, सूत्रकृतांग, भगवती, समवायांग,स्थानांग ग्रुप बनाकर पांच राउंड्स में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें क्रमश: आचारांग ग्रुप, सूत्रकृतांग और समवायांग ग्रुप को प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। सभी विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। संयोजिका सरिता संचेती का विशेष सहयोग रहा।

तेरापंथ सभा के अध्यक्ष अशोक चौधरी, जुगराज श्रीश्रीमॉल, महिला मंडल की अध्यक्ष ऊषा चौधरी, मंत्री लता नवलखा, तेयुप राजाजीनगर से अनिमेष चौधरी आदि उपस्थित थे।

अन्नदान

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

चेन्नई में चेंगलपेट के बीजेएस चैप्टर द्वारा बुधवार को महावीर जन्मकल्याणक के उपलक्ष्य में अस्पताल के बाहर अन्नदान किया गया। बीजेएस चैप्टर की अध्यक्ष सपना गडवानी के नेतृत्व में सदस्य दीपा मकाना, चन्दा, सुजीता गडवानी, मंजु, आशा, राजकुमारी मरलेचा, वसंती सांखला, पिंकी, अनिता कोठारी, किरण डूंगरवाल आदि ने अपनी सेवाएं दी।

कुछ उत्तरी जिलों में लू की वजह से कार्यालय के समय में बदलाव

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। कर्नाटक सरकार ने बुधवार को एक आदेश जारी कर गर्मी के मद्देनजर बेलगावी संभाग के विजयपुरा और बागलकोट जिलों तथा कलबुर्गी संभाग के सभी जिलों में अप्रैल से दो महीने के लिए सरकारी कार्यालयों में काम के घंटे में बदलाव किया है। इस संबंध में जारी आदेश के मुताबिक इन दो महीनों के दौरान सरकारी कार्यालय सुबह आठ बजे से दोपहर 1.30 बजे तक खुलेंगे।

परिपत्र में कहा गया कि कर्नाटक राज्य सरकारी कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार को एक प्रस्ताव दिया था कि उक्त जिलों में उच्च तापमान के कारण कर्मचारियों को अपने कर्तव्यों का पालन करने में होने वाली कठिनाई को देखते हुए अप्रैल और मई में कार्यालय के काम के घंटों में बदलाव किया जाए।

मासिक संगोष्ठी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

बेंगलूरु की आऊवा महिला मंडल की मासिक संगोष्ठी कांता रायसोनी के निवास पर उनकी अध्यक्षता में हुई। नवरात्रि थीम पर आयोजित इस संगोष्ठी में माता के गीत प्रस्तुत किए गए। इस बैठक में प्रभु महावीर के जीवन पर प्रश्नोत्तरी का भी आयोजन किया गया जिसमें सभी सदस्याओं ने भाग लिया। पिंकी इसरानी ने संचालन करते हुए सभी को धन्यवाद दिया।

सहयोग

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद द्वारा संचालित आचार्य तुलसी डायग्नोस्टिक सेंटर केंगेरी में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित महेंद्र मुणोत ने डायग्नोस्टिक सेंटर की स्वच्छता, व्यवस्था एवं सेवा के प्रति संतोष व्यक्त करते हुए 1लाख 25 हजार रुपए की सहयोग राशि का चैक प्रदान किया। तेरापंथ युवक परिषद राजराजेश्वरीनगर के अध्यक्ष विकास छाजेड़, मंत्री सुपारस पटावरी, पूर्व अध्यक्ष विकास छाजेड़, सरल पटावरी एवं अन्य सदस्यों ने मुणोत को सम्मानित किया।

विरोध प्रदर्शन

कर्नाटक प्रदेश महिला कांग्रेस की सदस्य अध्यक्ष सौम्या रेड्डी के नेतृत्व में बुधवार को बेंगलूरु में केंद्र सरकार से 33% महिला आरक्षण की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन करती हुई।

बिलावास गौशाला में 25 नम्बवर से होगी कृष्ण प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा

बेंगलूरु/दक्षिण भारत। राजस्थान के बिलावास गौशाला सेवा समिति के प्रतिनिधियों ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात कर उन्हें 25 नवम्बर से होने वाले बिलावास गौशाला में कृष्ण भगवान प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल होने का निवेदन करते हुए आमंत्रण दिया। प्रतिनिधिमंडल में बेंगलूरु निवासी व बिलावास सेवा समिति के अध्यक्ष इंदरचंद बोहरा सहित पदाधिकारी प्रतिनिधि मंडल ने राजस्थान के मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उनका सम्मान किया और गाय की प्रतिमा का स्मृति चिन्ह भेंट किया। पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को गौशाला में होने वाली विभिन्न गतिविधियों की जानकारी प्रदान की। ज्ञातव्य है कि गौशाला में लगभग 1200 गायों की देखरेख दानदाताओं के सहयोग से हो रही है ।

Published by Bhupendra Kumar on behalf of New Media Company, Arihant Plaza, 2nd Floor, 84-85, Wall Tax Road, Chennai-600 003 and printed by R. Kannan Adityan at Deviyin Kanmani Achagam, 246, Anna Salai, Thousand Lights, Chennai-600 006.
Regn No. RNI No. : TNHIN / 2013 / 52520 **Editor : Bhupendra Kumar** (Responsible for selection of news under PRB Act.). Group Editor - Shreekant Parashar.
Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any such manner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.